आजादी का पर्व
नए सपनों का संचार

देश मना रहा है 79वां स्वतंत्रता दिवस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से फहराएंगे तिरंगा

पेज 6-8

वर्ष: 6 अंक: 03

1-15 अगस्त, 2025 (नि:शुल्क)

न्यू इंडिया समाचार

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख

प्रगति-समृद्धि का नया युग

एक देश, एक प्रधान, एक विधान, एक निशान के दशकों पुराने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने और एकता के सूत्र में बांधने के छह वर्ष

आजादी का 'अगस्त' अध्याय

कुछ महीने, कुछ तारीखें इतिहास बन जाती हैं। उसके महत्व और मायने आने वाले कल में भी कम नहीं होते हैं। उनमें से एक है अगस्त का महीना। 78 साल पहले इसी माह की 15वीं तारीख को एक लंबे संघर्ष के बाद हमें आजादी मिली। इस संघर्ष और इसकी सफलता की नींव में भी अगस्त माह का खासा है योगदान...

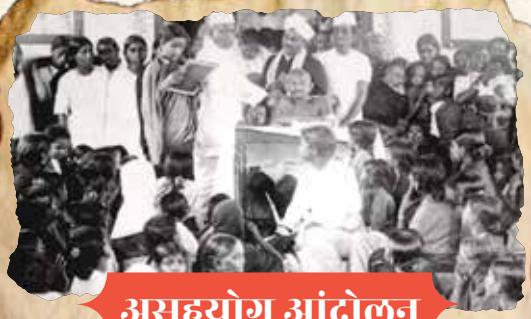

असहयोग आंदोलन

जिसने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिलाई

1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी।

इस आंदोलन के बाद लाखों कर्मी हड़ताल पर चले गए, छात्रों ने स्कूल-कॉलेज का बहिष्कार कर दिया।

1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद सबसे व्यापक पैमाने पर हुए इस आंदोलन ने अंग्रेजी राज की नींव हिला कर रख दी।

काकोरी ट्रेन एक्शन

स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक चिर स्मरणीय गाथा

लूट की रकम
4,669 रुपये, एक आना और 6 पाई।

9 अगस्त 1925 को रेल से ले जाए जा रहे सरकारी खजाने को रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने लखनऊ के नजदीक काकोरी रेलवे स्टेशन के पास लूट लिया था।

राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रौशन सिंह को फांसी की सजा दी गई। शचीन्द्रनाथ सान्याल को काले पानी और मन्मथनाथ गुप्त को 14 साल की सजा हुई।

भारत छोड़ो आंदोलन

आजादी की ओर सबसे बड़ा कदम

8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान पर 'करो या मरो' के नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया।

9 अगस्त को यह आंदोलन पूरे देश में शुरू हो गया।

लाखों भारतीय इस आंदोलन में कूद पड़े। जेलें ठसाठस भर गईं। इस आंदोलन की विराटता के साथ अगस्त माह से जुड़ाव को देखते हुए इसे 'अगस्त क्रांति' भी कहा जाता है।

न्यू इंडिया
समाचार

वर्षः 6, अंकः 03 । 1-15 अगस्त, 2025

प्रधान संपादक
धीरेन्द्र ओझा
प्रधान महानिदेशक
पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

मुख्य सलाहकार संपादक
संतोष कुमार

सलाहकार संपादक
विभोर शर्मा

वरिष्ठ सहायक सलाहकार संपादक
पवन कुमार

सहायक सलाहकार संपादक
अखिलेश कुमार
चन्दन कुमार चौधरी

भाषा संपादन
सुमित कुमार (अंग्रेजी)
रजनीश मिश्रा (अंग्रेजी)
नदीम अहमद (उर्दू)

चीफ डिजाइनर
श्याम तिवारी

सीनियर डिजाइनर
फूलचंद तिवारी

डिजाइनर
अभय गुप्ता
सत्यम सिंह

13 भाषाओं में उपलब्ध न्यू इंडिया समाचार को पढ़ने के लिए क्लिक करें।

https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

न्यू इंडिया समाचार के पुराने अंक पढ़ने के लिए क्लिक करें

https://newindiasamachar.pib.gov.in/archive.aspx

न्यू इंडिया समाचार के बारे में लगातार अपडेट के लिए फॉलो करें: @NISPIBIndia

अंदर के पन्नों पर...

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख

विकसित होने के संकल्प की सिद्धि की ओर अग्रसर

भेदभाव भरे 6 दशक के सिलसिले के खात्मे की 6वीं वर्षगांठ...अनुच्छेद 370 और 35ए की समाप्ति के बाद बदलाव की बयार के साथ विकास की मुख्यधारा में शामिल जम्मू-कश्मीर और लद्दाख | 10-25

डिजिटल स्वास्थ्य पहचान के साथ स्वस्थ भारत की नींव

भारत की स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल युग की शुरुआत के 5 वर्ष | 28-29

समाचार सार | 4-5

79वां स्वतंत्रता दिवस : आजादी के पर्व पर नए सपनों का संचार
पीएम मोदी लगातार 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज | 6-8

व्यक्तित्व - विक्रम साराभाई
भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक को 106वीं जयंती पर देश का नमन | 9

सहकार बेहतर कल का शक्तिशाली आधार
सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रखी पहले सहकारी विश्वविद्यालय की नींव | 26-27

रोजगार: युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की नींव
पीएम मोदी ने 51,000 से ज्यादा युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र | 37-38

केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय
देश के 100 जिलों के लिए प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना मंजूर | 39-40

ब्रिक्स के शिखर पर भारत

ढुनिया के सबसे शक्तिशाली मंचों में से एक ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी का संबोधन, साथ में उनका अब तक का सबसे बड़ा विदेश दौरा... | 30-36

प्रकाशक और मुद्रक: कंचन प्रसाद, महानिदेशक, सीबीसी (केंद्रीय संचार ब्यूरो)। **मुद्रण:** जेके ऑफसेट ग्राफिक्स प्रा. लि., बी-278, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020। **पत्राचार और ईमेल के लिए पता:** कमरा संख्या-316, नेशनल मीडिया सेंटर, रायसिना रोड, नई दिल्ली- 110001। **ईमेल-** response-nis@pib.gov.in आर. एन. आई. नंबर DELHIN/2020/78812

संपादक की कलम से...

विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख...

सादर नमस्कार।

मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं,
जिनके सपनों में जान होती है
पंखों से कुछ नहीं होता
हौसलों से उड़ान होती है

निःसंदेह, जब इरादे नेक हों, संकल्प को सिद्ध करने का जज्बा हो, तो फिर परिणाम भी मिलते हैं। भारत का गौरवशाली इतिहास सदैव ही वर्तमान को प्रेरित करता है- *एक बेहतर कल के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए।* अगस्त का महीना अब देश के लिए केवल आजादी की ही याद नहीं दिलाता, बल्कि सही अर्थों में भारत के एकीकरण और आखिरी छोर तक विकास की पहुंच की अनुभूति कराता है। अब स्वाधीनता समारोह सिर्फ प्रत्येक साल मनाए जाने वाले आजादी के उत्सव जैसा नहीं है, क्योंकि राष्ट्र विकसित भारत के संकल्प की ओर अग्रसर है। इस वर्ष 79वां स्वतंत्रता दिवस भविष्य के नए भारत की मजबूती और भरोसे का भी प्रतीक है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र ध्वज फहराएंगे।

केंद्र सरकार ने एक संकल्प लिया था- संकल्प से सिद्धि का। इन संकल्पों को साकार करने की दिशा में देश के बढ़ते कदम और *एक भारत-श्रेष्ठ भारत* की भावना ने देश की दिशा बदली है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने छह वर्ष पूर्व 5 अगस्त को दशकों के फासले को कम करते हुए विकास की दौड़ में पीछे छूट रहे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख से अनुच्छेद 370 और 35ए को निष्प्रभावी बनाकर ऐतिहासिक कदम उठाया था। इन भेदभावपूर्ण प्रावधानों से आजादी के बाद धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अब मुख्यधारा से जोड़ देश के अन्य राज्यों के बराबर लाकर खड़ा किया गया है। आज जम्मू-कश्मीर में देश का संविधान काम कर रहा है। केंद्र के सभी कानून अब जम्मू-कश्मीर में लागू हैं।

बीते 6 वर्ष में वक्त ने करवट ली है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख देश के विकास के साथ कदम से कदम मिला रहा है। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में अपना अमूल्य योगदान दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार के इस निर्णय को सही ठहराया, जिसने 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को मजबूत किया। एकता और सुशासन के लिए प्रतिबद्धता ही वर्तमान केंद्र सरकार की पहचान रही है, इसलिए स्वाधीनता के प्रतीक अगस्त महीने के पहले पखवाड़े के इस अंक में जम्मू-कश्मीर व लद्दाख में विकास की नई भोर ही हमारी आवरण कथा बनी है।

व्यक्तित्व की कड़ी में भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाने वाले डॉ. विक्रम साराभाई, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के पांच वर्ष की विकास यात्रा, देश के पहले सहकारिता विश्वद्यालय के शिलान्यास एवं 79वें स्वतंत्रता दिवस पर विशेष सामग्री, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत के शामिल होने के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा सहित उनके पखवाड़े भर के कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया है।

साथ ही, पत्रिका के इनसाइड में आजादी का 'अगस्त अध्याय' और बैक कवर पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को समाहित किया गया हैं।

आप अपना सुझाव हमें भेजते रहिए।

धीरेन्द्र

(धीरेन्द्र ओझा)

हिंदी, अंग्रेजी व अन्य 11 भाषाओं में उपलब्ध पत्रिका पढ़ें/डाउनलोड करें।
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

आपकी बात...

न्यू इंडिया समाचार पत्रिका से जिज्ञासुओं को बहुत लाभ

मुझे न्यू इंडिया समाचार पत्रिका पढ़ना बहुत पसंद है। यह पत्रिका हर क्षेत्र के बारे में, खासकर आज की तेजी से बदलती दुनिया में हमारे देश की प्रगति को समझने में बहुत उपयोगी लगती है। जिस तरह से जटिल मुद्दों को सरल भाषा में, आंकड़ा, तथ्य और दृश्यों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। उससे देश भर के जिज्ञासुओं को बहुत लाभ होता है। इतनी उच्च गुणवत्ता वाली, जानकारीपूर्ण सामग्री प्रदान करने के लिए संपादकीय टीम का धन्यवाद। मैं आगामी संस्करण का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।

एस.पी. सासनीजा
sp.sasnijaamrai@gmail.com

छात्रों के लिए काफी उपयोगी न्यू इंडिया समाचार पत्रिका

निःशुल्क मिलने वाली न्यू इंडिया समाचार पत्रिका पाकर काफी खुशी हुई। यह एक अच्छी पत्रिका है जिसमें पढ़ने के लिए बेहतरीन सामग्री रहती है। साथ ही, यह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी काफी उपयोगी है।

kadalnagarajan3@gmail.com

पत्रिका के माध्यम से विकास योजनाओं से निरंतर होता हूं अवगत

मैं पिछले एक साल से लगातार न्यू इंडिया समाचार पाक्षिक पत्रिका पढ़ रहा हूं। इस पत्रिका को पढ़ने में मेरी बहुत रुचि है। इसके माध्यम से मैं देश की जानकारी परक लेख और विकास योजनाओं से निरंतर अवगत होता हूं।

jaydipgiri.jjm@gmail.com

अत्यधिक ज्ञानवर्धक और प्रासंगिक है न्यू इंडिया समाचार पत्रिका

मुझे आपकी प्रतिष्ठित न्यू इंडिया समाचार पत्रिका मिली। यह मुझे जनता के बीच प्रमाणिक जानकारी प्रसारित करने के लिए अत्यधिक ज्ञानवर्धक और प्रासंगिक लगती है। सरकारी पहलों से लोगों को अपडेट रखने में आपके सराहनीय प्रयासों के लिए धन्यवाद। हमें आपके ऐसे अंकों में विशेष रूचि है जिसमें, सफलता की कहानी और नीतिगत निर्णयों को कवर किया जाता है। आपके ऐसे अंक हमारे जागरूकता अभियानों के लिए काफी उपयोगी हैं।

एम. नरेंद्र वर्मा
varma4388@gmail.com

न्यू इंडिया समाचार पत्रिका से मिलती है देश-विदेश की जानकारी

मैं न्यू इंडिया समाचार पत्रिका का नियमित पाठक हूं। मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पत्रिका को भव्य तरीके से प्रस्तुत किया। इस पत्रिका के माध्यम से देश-विदेश में होने वाली सभी घटनाओं से अवगत होता हूं। हर अंक से कुछ नया सीखने को मिलता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए न्यू इंडिया समाचार पत्रिका उपयोगी है।

ayushak596980@gmail.com

पत्राचार और ईमेल के लिए पता: कमरा संख्या-316,
नेशनल मीडिया सेंटर, रायसिना रोड, नई दिल्ली- 110001
ईमेल- response-nis@pib.gov.in

आकाशवाणी समाचार
Akashvani

न्यू इंडिया समाचार को आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर हर शनिवार-रविवार को दोपहर 3:00 से 3:15 बजे तक सुनने के लिए QR कोड स्कैन करें।

समाचार सार

रेलवन एप शुरू, रेलवे ने बढ़ाया सुविधा का एक और कदम

आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, विश्वस्तरीय यात्री सुविधाएं, कोने-कोने में कनेक्टिविटी और नए रोजगार सृजन के साथ उद्योगों को समर्थन का ध्येय लेकर भारतीय रेलवे आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवन एप लॉन्च किया। इस एप के जरिए यात्री 3 प्रतिशत छूट के साथ अनारक्षित और प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हैं। इसके साथ ही लाइव ट्रेन ट्रैकिंग, शिकायत निवारण, ई-कैटरिंग, पोर्टर बुकिंग और लास्ट माइल टैक्सी जैसी सुविधाएं भी प्राप्त कर सकते हैं। आईआरसीटीसी पर टिकटों का आरक्षण जारी रहेगा। रेलवन में सिंगल साइन-ऑन की सुविधा है, जिसमें एम-पिन या बायोमीट्रिक के जरिए लॉगिन किया जा सकता है। वहीं, सुरक्षा की दृष्टि से रेलवे अब हर कोच में सीसीटीवी कैमरे लगाने जा रहा है।

वैश्विक बाजार में भारतीय खिलौनों की धमक, 153 देश में हो रहा निर्यात

कभी आयात पर निर्भर रहने वाला भारत का खिलौना उद्योग अब घरेलू स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलने के बाद 153 देश में खिलौने निर्यात कर रहा है। अगस्त, 2020 में अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनमानस को झकझोरने वाली अपील की थी। साथ ही, 100% विदेशी निवेश की मंजूरी, टॉय क्लस्टर, विदेशी खिलौनों के आयात पर अनिवार्य प्रमाणन, राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना और ई-टॉयकथॉन 2025 जैसी पहल का परिणाम है कि भारत में 2014-15 के मुकाबले 2022-23 में खिलौनो के आयात में 52 फीसदी की कमी आई है। वहीं, निर्यात में 239 फीसदी की वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें टॉय बिज इंटरनेशनल बी2बी एक्सपो 2025 में केंद्र सरकार ने खिलौना क्षेत्र के लिए एक और नई प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य भारतीय खिलौना निर्माताओं की डिजाइन क्षमता को बढ़ाकर अच्छी क्वालिटी की मैन्युफैक्चरिंग को सुनिश्चित करना है।

रेलवे देगा 2 साल में 1 लाख से ज्यादा नौकरी

रेलवे भर्ती बोर्ड 2 साल में 1 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी देगा। इसके तहत वित्त वर्ष 2025-26 में 50 हजार से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाना है। इनमें से 9 हजार अभ्यर्थियों को इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में नियुक्ति दी जा चुकी है। अगले वित्त वर्ष यानी 2026-27 में भी 50 हजार भर्ती का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए पहले ही अधिसूचना जारी की जा चुकी है। बता दें कि 2024 से अब तक रेलवे 1.08 लाख रिक्तियों की घोषणा कर चुका है। वहीं, निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए रेलवे आधार प्रमाणीकरण का उपयोग कर रहा है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से नकल की गुंजाइश खत्म करने के लिए केंद्रों पर जैमर का उपयोग किया जा रहा है।

गौरवशाली क्षण...

यूनेस्को की सूची में भारत की 44वीं धरोहर मराठा सैन्य विरासत के 12 किले शामिल

भारत की मराठा सैन्य विरासत अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का हिस्सा बन गई है। इस धरोहर में 12 भव्य किले शामिल हैं, जिनमें से 11 महाराष्ट्र और 1 तमिलनाडु में स्थित है। विश्व धरोहर समिति की 47वीं बैठक में भारत के 'मराठा सैन्य परिदृश्य' यानी 'मराठा मिलिट्री लैंडस्केप' को सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया। इस सूची में शामिल होने वाली यह भारत की 44वीं धरोहर है। बीते 10 साल में 14 नई धरोहर को इसमें शामिल किया जा चुका है। यूनेस्को की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को बधाई दी। मराठा साम्राज्य के गढ़ रहे रायगढ़ के किले में 2014 में अपनी यात्रा की तस्वीरें साझा करते हुए उन्होंने कहा कि हर भारतीय इस सम्मान से उत्साहित है। मैं सभी से इन किलों को देखने और मराठा साम्राज्य के समृद्ध इतिहास के बारे में जानने का आह्वान करता हूं। बता दें कि धरोहर सूची में शामिल यह 12 किले मराठों ने 17वीं शताब्दी के अंत से लेकर 19वीं शताब्दी की शुरुआत के बीच बनवाए थे। रणनीतिक दृष्टि से किले को समुद्री तट और पहाड़ी इलाकों में बनाया गया था जो एक जटिल रक्षा प्रणाली का हिस्सा रहा था। यह मराठों की सैन्य शक्ति, व्यापार की सुरक्षा और क्षेत्रीय नियंत्रण के लिए जरूरी था।

महाराष्ट्र के शामिल किले

- सलहेर
- शिवनेरी
- लोहागढ़
- खंडेरी
- रायगढ़
- राजगढ़
- प्रतापगढ़
- स्वर्णदुर्ग
- पन्हाला
- विजयदुर्ग
- सिंधुदुर्ग

- तमिलनाडु स्थित जिंजी किला भी शामिल

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 7.14 करोड़ रुपये कराए वापस

आपने कोई उत्पाद खरीदा है और आपको उसे लेकर शिकायत है तो सीधे उपभोक्ता अदालत जाने की बजाय आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन से भी मदद ले सकते हैं। बीते दो महीने में ही राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने ऐसी 15 हजार से अधिक शिकायतों का निवारण किया है। इसमें से 10,373 शिकायत का निपटान करते हुए उपभोक्ताओं को 7.14 करोड़ रुपये वापस किए गए हैं। इसमें सबसे अधिक 8,919 शिकायत ई-कॉमर्स प्लेटफार्म की रहीं, जिसमें 3.69 करोड़ रुपये रिफंड कराए गए हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों से संबंधित विभाग की पहल है। यह हेल्पलाइन 17 भाषा में सेवा दे रही है। उपभोक्ता अपनी शिकायतें टोल-फ्री नंबर 1915, एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र (**INGRAM**), व्हाट्सएप (8800001915), एसएमएस (8800001915), ईमेल (**nch-ca@gov.in**), एनसीएच एप, वेब पोर्टल (**consumerhelpline.gov.in**) और उमंग एप के माध्यम से भेज सकते हैं।

दुनिया में सबसे तेज डिजिटल भुगतान करने वाला देश भारत : आईएमएफ

वर्ष 2016 में महज 21 बैंक के साथ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुआ भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) अब 600 से ज्यादा बैंक और 200 से ज्यादा एप के नेटवर्क को कवर कर रहा है। यूपीआई का दायरा इस तरह बढ़ा कि आज हर महीने 18 अरब से ज्यादा का लेनदेन हो रहा है। यह अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक खुदरा भुगतान तरीकों से आगे निकल चुका है। अपनी एक ताजा रिपोर्ट में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भी इसका लोहा माना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अब दुनिया का सबसे तेज डिजिटल भुगतान करने वाला देश बन गया है। इसी दौरान नकदी, डेबिट-क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल में गिरावट देखी गई है। आईएमएफ के अध्ययन में यह भी सामने आया है कि यूपीआई इंटरऑपरेबल मंच यानी किसी भी दूसरे बैंकिंग एप पर भुगतान की सीधी सुविधा की वजह से ही लेनदेन की संख्या के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी खुदरा फास्ट पेमेंट प्रणाली बन चुका है।

आजादी का पर्व नए सपनों का संचार

वर्ष 2014 में देश के जनमानस में ही बदलाव नहीं हुआ, बल्कि कई नई परंपराओं का भी उदय हुआ। ऐसे सुधारों की शुरूआत हुई, जिनका लंबे समय से देश को इंतजार था। सुधारों के इस सफर के साथ पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से शौचालय, स्वच्छता, सैनेटरी पैड जैसे शब्दों को इस्तेमाल कर वर्जनाएं ही नहीं तोड़ी, बल्कि आजादी के उत्सव को देश के नवनिर्माण से जोड़ ऐसी तमाम योजनाओं की शुरूआत की जो जनआंदोलन के रूप में स्वीकारी गईं। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर एक बार फिर देश को नए संकल्पों का इंतजार...

हर देश के इतिहास में कुछ क्षण ऐसे होते हैं, जो सिर्फ उसके आगे बढ़ने की यात्रा के मील के पत्थर ही नहीं होते, बल्कि भविष्य की सुनहरी उम्मीद की नींव भी होते हैं। आजादी की तारीख, 15 अगस्त 1947, एक ऐसी तारीख, जिस दिन देश ने सिर्फ आजादी का उजियारा ही नहीं देखा, बल्कि अपनी नियति के निर्माण की स्वतंत्रता भी हासिल की। यह प्रत्येक भारतीय को एक नई शुरूआत की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री पद संभालते ही नरेंद्र मोदी ने आजादी के जश्न की इस तारीख को देश की विकास यात्रा से जोड़ते हुए नए संकल्प की शुरुआत की। उन्होंने परंपराओं के नाम पर लंबे समय से ढोई जा रही व्यवस्थाओं को ही नहीं बदला, बल्कि आम बजट को एक महीने पहले पेश करने, "गिव इट अप" आंदोलन के जरिए लोगों को गैस सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रेरित करने जैसे जनआंदोलन की भूमि तैयार कर आजादी के जश्न के नए मानदंड भी स्थापित किए।

स्वतंत्रता दिवस को एक संकल्प का रूप देकर उसे जन-जन से जोड़ने की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के अपने पहले संबोधन से ही कर दी थी। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से स्वच्छता और हर घर में शौचालय बनवाने का बीड़ा उठाया। अक्सर लाल किले से देश बड़ी घोषणाओं का इंतजार करता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता की बात कर उसे सही मायने में जन आंदोलन बना दिया।

लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ही बतौर प्रधानमंत्री 'मेक इन इंडिया' का आह्वान

आजादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव

आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न धूमधाम से मनाने और जन-जन में उत्सव का भाव भरने के लिए दांडी यात्रा की प्रेरणा से 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम से आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई। महोत्सव 31 अक्टूबर 2023 को सरदार पटेल की जयंती पर "मेरी माटी मेरा देश" अभियान के साथ संपन्न हुआ। इसमें न केवल सरकार, बल्कि समाज का दृष्टिकोण अपनाया गया। 2 वर्ष से अधिक चले अमृत महोत्सव के समारोह में वैश्विक स्तर पर प्रवासी भारतीय और 150 से अधिक देश के लोग भी शामिल हुए। महोत्सव के तहत करीब 2.25 लाख छोटे-बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए।

"मेरी माटी मेरा देश"

भारत के युवा कैसे संगठित होकर हर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है 'मेरी माटी मेरा देश' अभियान। इस अभियान के तहत गांव-गांव, गली-गली से युवा जुड़े और अनगिनत भारतीयों ने अपने हाथों से अपने आंगन और खेत की मिट्टी अमृत कलश में डाली। देश भर से साढ़े आठ हजार कलश 31 अक्टूबर 2023 को कर्तव्य पथ पर पहुंचे। इस अभियान के तहत करोड़ों भारतीय ने पंच प्रण की प्रतिज्ञा ली।

मिट्टी ही क्यों? एक कवि ने कहा है-

यह वह मिट्टी जिसके रस से, जीवन पलता आया,
जिसके बल पर आदिम युग से,मानव चलता आया।
यह तेरी सभ्यता संस्कृति, इस पर ही अवलंबित,
युगों-युगों के चरण चिह्न, इसकी छाती पर अंकित।

किया, जिससे इसका महत्व देश ने समझा। पीएम मोदी ने कहा था, "मेक इन इंडिया के लिए आगे बढ़ें। ऐसी वस्तु नहीं बनाएंगे जिसमें डिफेक्ट हो, ताकि दुनिया के बाजार से वापस न आएं। ऐसी वस्तु बनाएंगे जिसका पर्यावरण पर जीरो इफेक्ट हो या नेगेटिव इफेक्ट न हो।" मैन्युफैक्चरिंग पर अधिक जोर देने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर समीक्षा के बाद मेक इन इंडिया 2.0 शुरू किया। देश की वित्तीय धारा से दूर गरीबों को वित्तीय धारा में लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री जन-धन योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य प्रत्येक भारतीय का बैंक खाता खोलना था। फिर जनधन-आधार-मोबाइल की त्रिमूर्ति ने सीधे खाते में लाभ भेजने का रास्ता आसान बना दिया।

वर्ष 2015 में स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया की घोषणा भी पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में की। आज एक लाख से अधिक स्टार्टअप के साथ भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश है तो स्टैंडअप इंडिया में 60 लाख करोड़ रुपये से अधिक के लोन उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए दिए गए हैं। 2016 में गरीबों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी। यह योजना 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को धुआं मुक्त रसोई प्रदान करने में एक बड़ा कदम साबित हुई है। आजादी के 70 वर्ष के बाद भी 18,000 गांव ऐसे थे, जहां बिजली नहीं थी। वहां बिजली पहुंचाई गई है। करोड़ों लोगों को अपना पक्का घर देने के वादे पर सरकार कदम आगे बढ़ा रही है और अभी तक 4 करोड़ से अधिक घर देकर प्रधानमंत्री के 'हाउसिंग फॉर ऑल' के सपने को पूरा किया जा रहा है।

यही नहीं, यह विडंबना ही थी कि आजादी के 7 दशक बाद

स्वतंत्रता दिवस पर सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड भी पीएम मोदी के नाम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्र को 98 मिनट तक संबोधित किया। लाल किले की प्रचीर से देश के किसी भी प्रधानमंत्री का यह सबसे लंबा भाषण है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरु ने अपना सबसे लंबा भाषण 1947 में 72 मिनट का दिया था।

नई शुरुआत...

- वर्ष 2023 में पहली बार विभिन्न योजना और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेष लोगों को आमंत्रित किए जाने की शुरुआत। इसमें 1,800 विशिष्ट लोग बुलाए गए। वर्ष 2024 में 6,000 विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया गया।
- आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में पहली बार स्वदेश निर्मित होवित्जर तोप, एडवांस्ड टो आर्टिलरी गन सिस्टम (एटीएजीएस) से 21 तोप की सलामी दी गई।
- आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 7,500 वर्ग फुट के राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन देश के तमाम हिस्से में किया गया। ध्वज अंटार्कटिका में भी प्रदर्शित किया गया जो अंटार्कटिका में किसी भी देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का विश्व रिकॉर्ड बना।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से रिकॉर्ड 12वीं बार झंडा फहराएंगे।

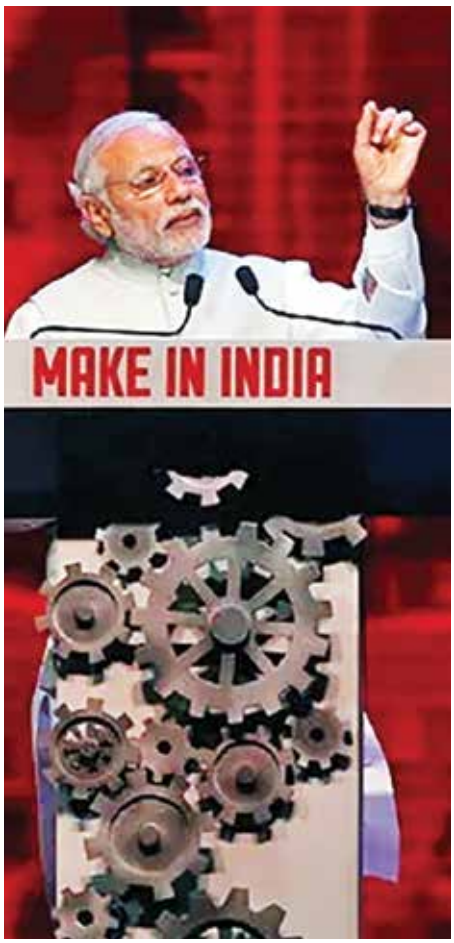

भी केवल 3.23 करोड़ ग्रामीण घरों में ही नल कनेक्शन थे। गांवों में एक बड़ी आबादी पारंपरिक स्रोत और गंदे पानी से होने वाली बीमारियों के बोझ तले दबी हुई थी। इस समस्या के समाधान के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से 5 वर्ष में हर घर नल से जल पहुंचाने के संकल्प का एलान किया था। स्वतंत्रता दिवस 2015 पर लाल किले की प्राचीर से निचले ग्रेड की नौकरियों में साक्षात्कार समाप्त करने की घोषणा की। 1 जनवरी, 2016 से भारत सरकार ने सभी मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में समूह 'घ' और 'ग' के साथ समूह 'ख' (अराजपत्रित) व समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार खत्म कर दिया। भारत को 2047 तक एक ऊर्जा संपन्न राष्ट्र बनाने के लिए नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा भी प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2021 को लाल किले की प्राचीर से ही की। ▪

भारत को अंतरिक्ष तक ले जाने वाले नायक

अहमदाबाद के प्रसिद्ध कपड़ा मिल मालिक और समाजसेवी अंबालाल साराभाई के घर 12 अगस्त 1919 को एक बच्चे ने जन्म लिया। घर पर भारत के चोटी के बुद्धिजीवी और वैज्ञानिकों की बैठक जमा करती थी। एक दिन गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर भी आए। कहते हैं गुरुदेव को उन दिनों माथा देखकर भविष्यवाणी करने का शौक था। बच्चे को उनके सामने लाया गया। चौड़ा ललाट देख गुरुदेव बोले, "ये बच्चा एक दिन बहुत बड़े काम करेगा।" आगे चलकर उनकी वाणी सच साबित हुई। इस बच्चे का नाम था, विक्रम साराभाई। जिन्होंने सिर्फ बड़ा काम ही नहीं किया, बल्कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा की नींव भी रखी...

जन्म : 12 अगस्त 1919 ■ मृत्यु : 31 दिसंबर 1971

बचपन से ही विक्रम साराभाई विज्ञान की बारीकी और मशीन की दुनिया की ओर आकर्षित होने लगे थे। मां सरलादेवी ने मांटेसरी स्कूल खोला। बालक विक्रम की प्रारंभिक शिक्षा-दीक्षा यहीं हुई। बाद में 1937 में ब्रिटेन में कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज में दाखिला ले लिया। वहां से वर्ष 1940 में प्राकृतिक विज्ञान में ट्राइपोस करके निकले। यह द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। इसलिए विक्रम भारत लौट आए और बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान से जुड़ गए। यहां उन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त डॉ. चंद्रशेखर वेंकट रमन की निगरानी में कॉस्मिक किरणों का अध्ययन शुरू किया। विश्वयुद्ध की समाप्ति पर साराभाई दोबारा कैंब्रिज गए और कॉस्मिक किरण भौतिकी में पीएचडी की डिग्री हासिल की। वर्ष 1947 में स्वदेश लौट आए। इसी साल उन्होंने अहमदाबाद में 'भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला' (पीआरएल) की स्थापना की। उस समय उनकी उम्र केवल 28 वर्ष थी। रूसी स्पुतनिक प्रक्षेपण के बाद 1957 में उन्होंने अंतरिक्ष कार्यक्रम के विकास और भारत के हित में उसके उपयोग पर सबका ध्यान खींचा। साराभाई के प्रयासों से 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति (INCOSPAR) की स्थापना की गई। 15 अगस्त 1969 को इसे पुनर्गठित कर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के तौर पर स्थापित किया गया। नासा के साथ उनके संपर्क ने 1975 में सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टीवी एक्सपेरिमेंट का मार्ग प्रशस्त किया, जिसने भारत में केबल टीवी की शुरुआत की।

साराभाई को संस्थानों को गढ़ने में भी महारत हासिल थी। टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी से उनका वास्ता न था, लेकिन उन्होंने अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन(अतिरा) जैसी संस्था खड़ी कर दी। इस संस्था ने भारत में वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण में अहम भूमिका निभाई। भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला (हैदराबाद), विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (तिरुअनंतपुरम), फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर (कल्पक्कम), परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन परियोजना (कोलकाता), भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लि. (हैदराबाद), भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड (जादूगोड़ा, झारखंड) भी उन्हीं की देन हैं। 1966 में विमान हादसे में डॉ. होमी जहांगीर भाभा के निधन के बाद देश के विज्ञान जगत में जो खालीपन आ गया था उसे साराभाई ने अपनी कुशलता और नेतृत्व क्षमता से न सिर्फ भरा, बल्कि अंतरिक्ष के साथ देश के परमाणु कार्यक्रम को भी नया आयाम दिया।

मिसाइलमैन के तौर पर पहचाने जाने वाले पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की प्रतिभा निखारने में भी साराभाई का ही हाथ था। 1947 और 1971 के बीच साराभाई के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विज्ञान पत्रिकाओं में उनके 85 से ज्यादा शोध पत्र प्रकाशित हुए। उन्हें 1962 में शांति स्वरुप भटनागर पदक प्रदान किया गया था। 1966 में साराभाई को पद्म भूषण और 1972 में पद्म विभूषण (मरणोपरांत) से सम्मानित किया गया। केरल के कोवलम के एक होटल में 31 दिसंबर 1971 को नींद में ही विक्रम साराभाई की मृत्यु हो गई। उस समय भी उनके सीने पर एक किताब पड़ी हुई थी। 17 जनवरी 2019 को पीएम मोदी ने अहमदाबाद में साराभाई की प्रतिमा का अनावरण उनके परिवार की उपस्थिति में किया था। ■

अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने के 6 वर्ष

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख

विकसित होने के संकल्प की सिद्धि की ओर अग्रसर

नए भारत की सोच, नीति, रणनीति, जनकल्याण से राष्ट्र कल्याण और जन अभियान से राष्ट्र निर्माण की है। ऐसे में 'एक-भारत-श्रेष्ठ भारत' की अवधारणा के साथ जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों का विकास केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बन चुकी है। छह वर्ष पूर्व 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर ऐतिहासिक भूल को सुधारते हुए परिवर्तनकारी सुधार की नई गाथा लिखी थी, जिससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख विकास के नए मानक तय कर रहा है। पहले जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में चंद लोगों तक सीमित रहने वाला शासन अब एक लोकाभिमुख शासन के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है।

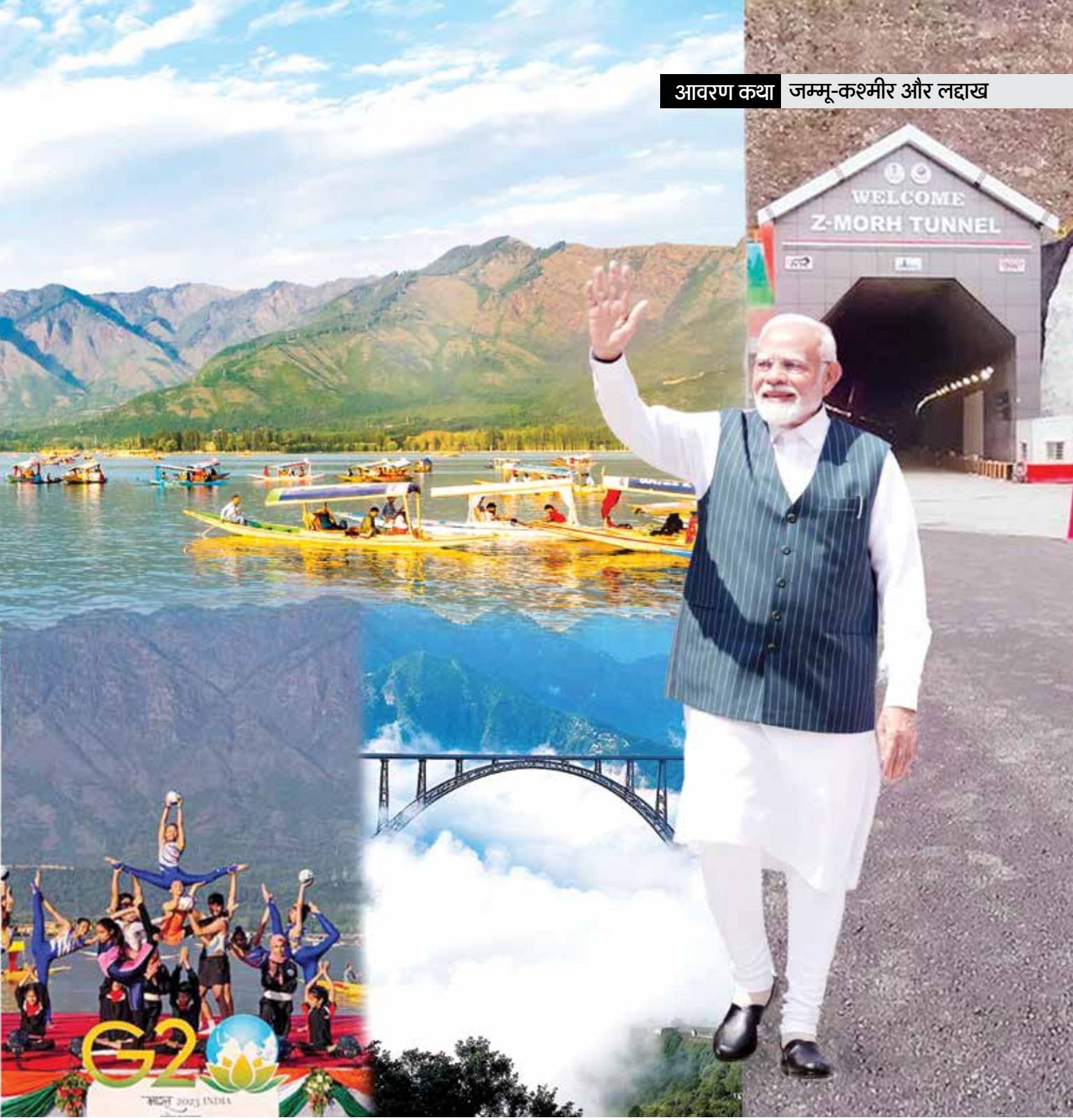

छह दशक से अधिक की दूरी को वर्तमान केंद्र सरकार ने अपने 6 वर्ष से कम समय में ही खत्म किया है। इस 5 अगस्त को उस ऐतिहासिक दिन के 6 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि कैसे इन 6 वर्ष में प्रगति और समृद्धि के एक नए युग की ओर बढ़ा है जम्मू-कश्मीर और लद्दाख...

"हमारे लिए 5 अगस्त का निर्णय अटल है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को नए रास्ते पर ले जाने का निश्चय भी अटल है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर में भारत का पूरा संविधान और कानून लागू हुआ, 70 साल से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास में जो सबसे बड़ी रुकावट थी, वो हमने 5 अगस्त को हटा दी।"

यह उद्घोष है उस नए भारत के नेतृत्व का, जो ठान चुका है कि उसे अतीत के अनावश्यक बंधनों में बंधकर नहीं रहना है। आज नया भारत, अपने वर्तमान को मजबूत तो कर ही रहा है, स्वयं को भविष्य के लिए भी तैयार कर रहा है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को लेकर लिया गया 6 वर्ष पूर्व का निर्णय वर्तमान केंद्र सरकार के संस्कारों का दर्पण है, जिसके वादों और इरादों में एक स्पष्टता भी है और उसे पूरा करने का साहस-सामर्थ्य भी। दशकों से चली आ रही जिस समस्या को सुलझाना असंभव माना जाने लगा था, उसे 5 अगस्त 2019 को राष्ट्र ने साकार करके अभूतपूर्व कदम उठाया।

दरअसल, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केवल एक राज्य या जमीन का टुकड़ा भर नहीं है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का मस्तक है। वहां का समूचा जीवन, वहां का कण-कण, भारत की सोच को, भारत की शक्ति को मजबूत करता है। एक देश, एक विधान, एक निशान का सपना साकार हुआ है तो अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के हटने के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख विकसित होने के संकल्प की सिद्धि के मार्ग पर अग्रसर है। इस 5 अगस्त को देश के इतिहास में महत्वपूर्ण क्षण के छह साल पूरे हो रहे हैं, जब भारतीय संसद ने अनुच्छेद 370 और 35 (ए) को निरस्त करने का फैसला किया था। यह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में प्रगति एवं समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत थी। इसका मतलब था कि भारत के संविधान को इन जगहों पर अक्षरशः लागू किया जाएगा, जो महान संविधान निर्माताओं की दृष्टि के अनुरूप है। अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान के करीब 66 वर्ष बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प से साकार हुआ एक देश-एक प्रधान-एक विधान-एक निशान का सपना

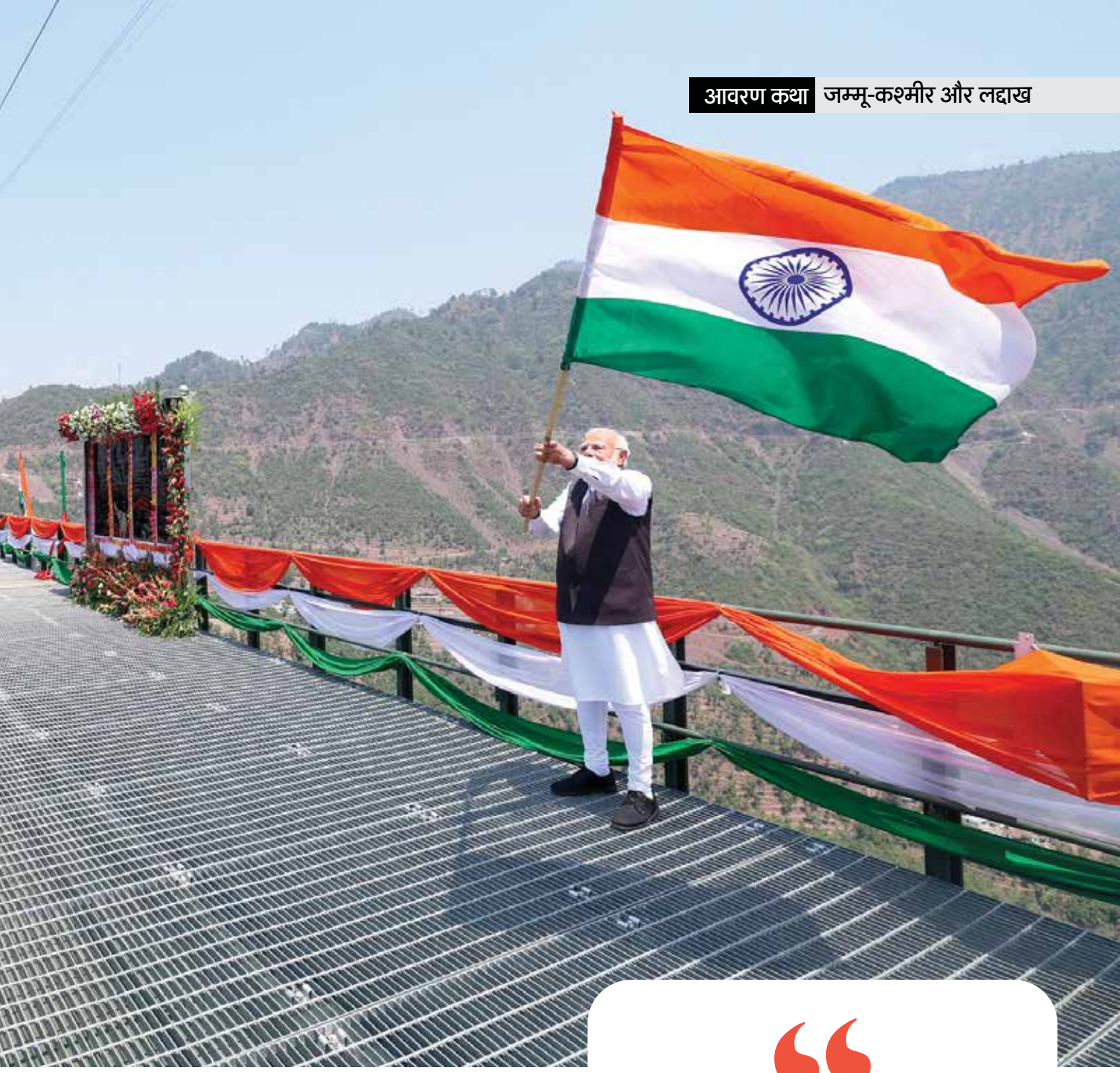

साथ विकास के लाभ से वंचित समुदाय के लिए सुरक्षा, सम्मान और नए अवसर आए तो वहीं साथ ही, इसने दशकों से जम्मू-कश्मीर में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर रखना भी सुनिश्चित किया है।

ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि अनुच्छेद 370 और 35ए को दशकों तक बनाए रखने का क्या कारण था? क्यों वहां के नागरिकों को उनके मूल अधिकारों से वंचित रखा गया था? लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार की पहचान है - समस्याओं को न टालते हैं और न ही पालते हैं। जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुआ, 2019 में दूसरी बार

“

मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जम्मू-कश्मीर के दुश्मनों को सबक सिखाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। यहां की नई पीढ़ी, स्थायी शांति के साथ ही जिएगी। जम्मू-कश्मीर ने तरक्की का जो रास्ता चुना है, उस रास्ते को हम और मजबूत करेंगे।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नई सरकार बनने के 70 दिन के भीतर-भीतर हुआ। भारत की संसद ने दो तिहाई बहुमत से अनुच्छेद 370 और 35ए हटाने संबंधी बिल को पास कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि इसका मतलब यह हुआ कि हर किसी के दिल में यह बात थी, लेकिन प्रारंभ कौन करे, आगे कौन आये, शायद उसी का इंतजार था और देशवासियों ने उन्हें यह काम दिया और उसे उन्होंने पूरा किया।

सामाजिक न्याय की दिशा में बढ़े कदम

जम्मू-कश्मीर में आ रहा यह बदलाव केंद्र सरकार की बीते 10-11 साल की कोशिशों का परिणाम है। शरणार्थी परिवार हों, वाल्मीकि समुदाय हों, सफाई कर्मचारी हों, सबको लोकतांत्रिक हक मिला है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' का यही मंत्र विकसित जम्मू-कश्मीर की बुनियाद है। पाकिस्तान से आए शरणार्थी, वाल्मीकि समुदाय और सफाई कर्मचारियों के परिवार को पहली बार स्थानीय निकाय चुनाव में वोट डालने का अधिकार मिला है। वाल्मीकि समुदाय को एससी कैटेगरी का लाभ मिलने की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। पहली बार एसटी समुदाय के लिए विधानसभा में सीटें आरक्षित की गई हैं। 'पद्दारी जनजाति', 'पहाड़ी जातीय समूह', 'गड्डा ब्राह्मण' और 'कोली' इन सभी समुदायों को भी एसटी का दर्जा दिया गया है। पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण पहली बार लागू हुआ है। कश्मीर में जब अनुच्छेद 370 और 35ए लागू था, तब वहां महिलाएं कई अधिकारों से वंचित थीं। अगर वो राज्य के बाहर किसी से शादी कर लेती थीं, तो पुश्तैनी संपत्ति पाने का उनका अधिकार छिन जाता था। इस अनुच्छेद की दीवार गिरने के बाद जम्मू-कश्मीर में भी महिलाओं को वो सारे अधिकार मिले हैं, जो भारत के अन्य राज्य की महिलाओं को मिलते हैं। इतना ही नहीं, दशकों तक जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को संविधान के अधिकारों से वंचित रखा गया। यह संविधान के साथ भी अन्याय था और जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के लोगों के साथ भी। अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के निवासियों को भी अन्य राज्यों के नागरिकों की तरह ही अधिकार मिले हैं क्योंकि देश की एकता वर्तमान केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। पीएम आवास योजना में बन रहे घरों में से अधिकांश का मालिकाना हक महिलाओं के नाम है। हर घर नल से जल योजना, हजारों की संख्या में शौचालयों के निर्माण, आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज ने यहां के लोगों का जीवन बहुत आसान बनाया है। भारत के संविधान में जिस सामाजिक न्याय का भरोसा दिया गया है, वो भरोसा पहली बार जम्मू-कश्मीर के सामान्य जन को भी मिला है।

शहरी विकास

200 ई-बस शुरू हुईं पीएम ई-बस सेवा के तहत। 200 और ई-बस शुरू की जा रही हैं।

अमृत-I में 82 परियोजना पूरी, अमृत-II में 1665.10 करोड़ रु.की लागत वाली 153 परियोजना स्वीकृत।

स्मार्ट सिटी मिशन

261 परियोजना का काम पूरा।

26 परियोजना पर काम जारी।

47,040 घर पीएमएवाई (यू) में मंजूर, 30,700 घर का निर्माण पूरा।

ग्रामीण विकास

3.35 लाख मकान पीएम आवास योजना ग्रामीण में स्वीकृत, 3.07 लाख का निर्माण पूरा।

स्वच्छ भारत मिशन

100% गांवों को ओडीएफ प्लस का दर्जा।

45% पंचायत प्लास्टिक मुक्त।

477 भूमिहीन परिवार को 5-5 मरला जमीन आवंटित की जा रही है।

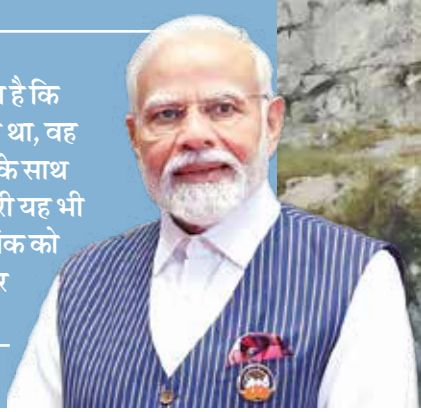

"मेरा हमेशा से दृढ़ विश्वास रहा है कि जम्मू-कश्मीर में जो कुछ हुआ था, वह हमारे राष्ट्र और वहां के लोगों के साथ एक बड़ा विश्वासघात था। मेरी यह भी प्रबल इच्छा थी कि मैं इस कलंक को मिटाने के लिए जो कुछ भी कर सकता हूं, उसे जरूर करूं।

– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

समृद्धि-शांति-प्रगति के पथ पर अग्रसर

अनुच्छेद 370 के भेदभावपूर्ण प्रावधानों से आजादी के बाद धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अब मुख्यधारा

तरक्की को रफ्तार देती कनेक्टिविटी

रास्तों को नई रफ्तार...

सड़क संपर्क

61,528 करोड़ रुपये का निवेश सड़क संपर्क के लिए किया गया। यात्रा आसान और समय की बचत हुई।

3,685 करोड़ रु. की लागत से अखनूर-पुंछ सड़क के दोहरीकरण का काम जारी।

3,132 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 8.45 किलोमीटर जुड़वां काजीगुंड-बनिहाल सुरंग का निर्माण। इसकी वजह से जम्मू से श्रीनगर की यात्रा अब 8-10 घंटे की बजाय 5-6 घंटे में पूरी हो जाती है।

8,000 कि.मी. से अधिक सड़क का निर्माण बीते 4 वर्ष में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किया गया।

302 पुल का निर्माण पिछले चार वर्ष में उन बसावटों को जोड़ने के लिए किया गया जो अभी तक जुड़े नहीं थे।

250 से अधिक आबादी वाली 99% बस्तियों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से जोड़ा गया।

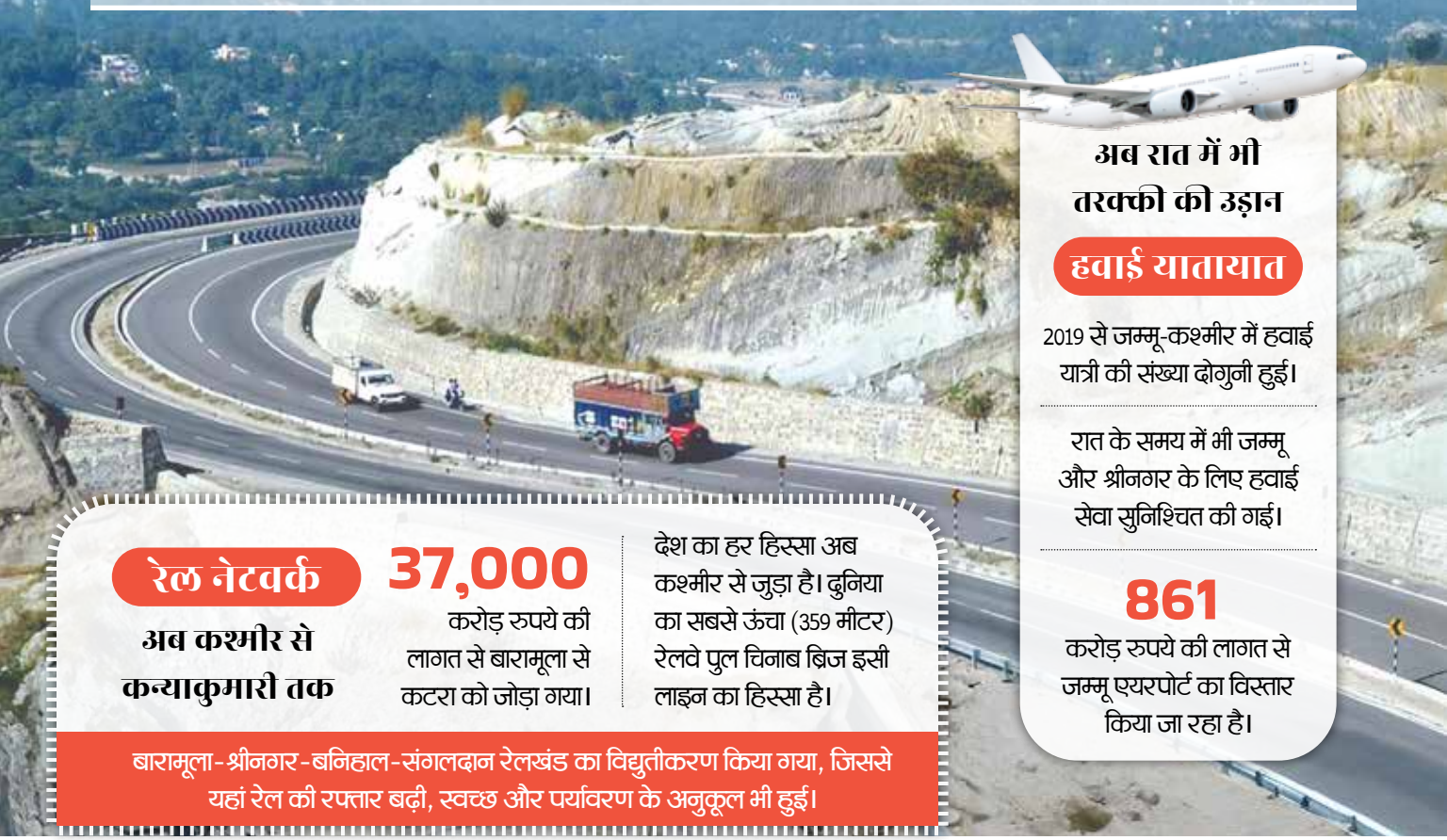

रेल नेटवर्क

अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक

37,000 करोड़ रुपये की लागत से बारामूला से कटरा को जोड़ा गया।

देश का हर हिस्सा अब कश्मीर से जुड़ा है। दुनिया का सबसे ऊंचा (359 मीटर) रेलवे पुल चिनाब ब्रिज इसी लाइन का हिस्सा है।

बारामूला-श्रीनगर-बनिहाल-संगलदान रेलखंड का विद्युतीकरण किया गया, जिससे यहां रेल की रफ्तार बढ़ी, स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल भी हुई।

अब रात में भी तरक्की की उड़ान

हवाई यातायात

2019 से जम्मू-कश्मीर में हवाई यात्री की संख्या दोगुनी हुई।

रात के समय में भी जम्मू और श्रीनगर के लिए हवाई सेवा सुनिश्चित की गई।

861 करोड़ रुपये की लागत से जम्मू एयरपोर्ट का विस्तार किया जा रहा है।

से जोड़ देश के अन्य राज्यों के बराबर लाकर खड़ा किया गया है। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद 890 केंद्रीय कानून अमल में लाए गए, राज्य के 205 कानून रद्द किए गए और 130 कानून को सुधार कर लागू किया गया। सुरक्षित अधिकार, सशक्त जीवन की दिशा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है तो 15 नई ओबीसी जातियों का आरक्षण लाभ 4 से बढ़ाकर 8 प्रतिशत किया गया। साथ ही, 10 प्रतिशत आरक्षण पहाड़ी, पद्दारी, कोईल, गड्डा ब्राह्मणों को मिलने लगा है। ऐसे में एक-भारत-श्रेष्ठ भारत की अवधारणा के साथ जम्मू-कश्मीर-लद्दाख के लोगों का विकास केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बन चुका है। चाहे महिला सशक्तीकरण हो, युवाओं के लिए अवसर की बात हो, अनुसूचित जाति-जनजाति-पीड़ित-शोषित-वंचितों के कल्याण का लक्ष्य हो या फिर लोगों के संवैधानिक और बुनियादी अधिकार, आम जन की भलाई के लिए सरकार हरसंभव फैसले ले रही है। जनहित से जुड़े

सिंचाई

झेलम और सहायक नदियों के लिए बाढ़ प्रबंधन की योजना

399
करोड़ रुपये की लागत से पहले फेज का काम पूरा।

1,623
करोड़ रुपये की लागत से दूसरे फेज का काम जारी।

- 62 करोड़ रुपये की लागत से मुख्य रावी नहर का काम पूरा किया गया।
- तवी बैराज प्रोजेक्ट को 8 वर्ष बाद दोबारा शुरू किया गया। पर्यटन के लिए कृत्रिम झील निर्माण का 84% काम पूरा हुआ।

शाहपुरकंडी बांध का 1979 से लंबित विवाद सुलझा

1,150 क्यूसेक पानी रावी नदी से जम्मू-कश्मीर को मिलेगा। इसके तहत रावी नहर के अधूरे हिस्से का 96 प्रतिशत काम पूरा।

- 32,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई की व्यवस्था, सांबा और कठुआ क्षेत्र के लोगों को लाभ।
- 170 करोड़ रुपये की लागत से त्राल लिफ्ट सिंचाई योजना का काम पूरा, 5,122 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई व्यवस्था की गई।
- 60 करोड़ रुपये की लागत से मार्च 2021 में रावी नहर के आधुनिकीरण का काम पूरा किया गया। वितरण प्रणाली मजबूत हुई है।

जल शक्ति

13,000
करोड़ रुपये की लागत से 3,266 जल जीवन मिशन परियोजना क्रियान्वित की जा रही है।

15.60
लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल कनेक्शन दिए गए, 2019 में सिर्फ 5.78 लाख कनेक्शन थे।

अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख पहली बार राष्ट्र की मुख्यधारा में पूरी तरह से एकीकृत हुए। परिणामस्वरूप, भारत के संविधान में निहित सभी अधिकार और सभी केंद्रीय कानूनों के लाभ, जो देश के अन्य नागरिकों को हासिल थे, वह अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को भी मिल रहे हैं।

केंद्रीय कानूनों को दोनों केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया गया, ताकि लोगों को इसका लाभ मिले और राज्य की प्रगति तेज हो। कमजोर वर्ग, बच्चे और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कानून को मजबूती मिली तो सुशासन के लिए जरूरी कानूनों को प्रभावी बनाया गया, ताकि प्रशासन जवाबदेह बने। अंतिम छोर तक लोकतंत्र को मजबूती देने वाले संविधान संशोधन (73वां और 74वां) अब पूरी तरह से राज्य में लागू हो चुके हैं, जिससे पंचायत और स्थानीय निकायों को सशक्त किया गया है। जम्मू-कश्मीर देश का एकमात्र राज्य है, जहां सभी नागरिकों को 'आयुष्मान योजना-सेहत' के तहत 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है।

बदला माहौल, देख रही दुनिया

कश्मीर घाटी में जो बदलाव हुए हैं, आज पूरी दुनिया उन्हें देख रही है। जी-20 समूह में जो लोग यहां आए थे, वह भी कश्मीर की प्रशंसा करते हैं। श्रीनगर में जी-20 जैसा अंतरराष्ट्रीय आयोजन हर कश्मीरी का सीना गर्व से भर देता है। आज जब लाल चौक पर देर-शाम तक बच्चे खेलते-खिलखिलाते हैं तो हर भारतीय आनंद से भर जाता है। आज जब यहां के सिनेमा हॉल और बाजारों में रौनक दिखती है तो

परिसीमन

90 विधानसभा सीट हुईं 83 से बढ़कर परिसीमन के बाद।

24 विधानसभा सीट पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के लिए अलग से सुरक्षित रखी गई हैं।

9 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए पहली बार जम्मू-कश्मीर विधानसभा में सुरक्षित।

मतदान 2024

लोकसभा	विधानसभा
58.46%	63%

आरक्षण

- जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 में संशोधन कर 9 जुलाई 2019 को अधिसूचना जारी की गई। इसके अनुसार वास्तविक नियंत्रण रेखा से सटे क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को सीधी भर्ती, पदोन्नति और पाठ्यक्रमों में मिलने वाले 3% आरक्षण को बढ़ाकर न सिर्फ 4% किया गया, बल्कि इसका लाभ अब अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी दिया गया।
- जम्मू-कश्मीर राजभाषा अधिनियम 2020 को अधिसूचित किया गया। इसके अनुसार 27 सितंबर 2020 से कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी भाषा को केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया।
- डोमिसाइल कानून में संशोधन किया गया। पहले जो समुदाय वंचित थे, उन्हें पात्र बनाया गया। साथ ही डोमिसाइल प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन और आसान बनाया गया।
- जम्मू में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की एक पीठ स्थापित की गई है।

ऊर्जा

- 5,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य अगले पांच वर्ष में।
- 1,600 मेगावाट सौर ऊर्जा के लिए पहली बार सौर ऊर्जा खरीद पर करार किया गया।
- 38 ग्रिड स्टेशन और 266 सब-स्टेशन का निर्माण।
- 467 किलोमीटर नई ट्रांसमिशन लाइन बिछाई गई।
- 7.27 लाख स्मार्ट बिजली मीटर लगाए गए।

3,014 मेगावाट क्षमता की चार मेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट 2026 तक पूरा होने की उम्मीद।

सबके चेहरे खिल उठते हैं। केंद्र सरकार ईमानदारी और समर्पण भाव से राज्य के विकास में जुटी है, ताकि कश्मीर की पिछली पीढ़ियों ने जो भुगता, उससे बाहर निकलने का रास्ता बनाया जा सके। दूरियां चाहे दिल की रही हों या फिर दिल्ली की, हर दूरी को मिटाने की कोशिश हो रही है। कश्मीर में जम्हूरियत का फायदा हर इलाके, हर परिवार को मिले, हर किसी की तरक्की हो, इसके लिए सबको साथ लेकर काम किया जा रहा है। आज केंद्र सरकार से आई हुई पाई-पाई राज्य की भलाई के लिए खर्च होती है। जिस काम के लिए पैसा दिल्ली से निकला है, उसी काम के लिए वो पैसा लगे और उसका परिणाम भी नजर आए, यह सुनिश्चित किया जा रहा है।

रोड और रेल कनेक्टिविटी हो, एजुकेशन और हेल्थ से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर बिजली-पानी, हर मोर्चे पर जम्मू-कश्मीर में बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत यहां हजारों किलोमीटर नई सड़कें बनी हैं। जम्मू कश्मीर में नए-नए नेशनल हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। चिनाब

सुरक्षित जम्मू-कश्मीर

पत्थरबाजी की घटनाएं

2023 अप्रैल: 0 (100% की कमी)

2018: 1,328

संगठित हड़ताल और बंद की घटनाएं

2023 अप्रैल: 0 (100% की कमी)

2018: 52

संघर्ष विराम उल्लंघन के मामले

2024: 4 (99.8% की कमी)

2018: 390

आतंकवादी घटनाओं की संख्या

2024: 27 (88% की कमी)

2018: 228

शहीद होने वाले सुरक्षाकर्मियों की संख्या

2024: 31 (66% की कमी)

2018: 91

आतंकवादी घटना और मुठभेड़ में मारे गए नागरिक

2024: 26 (53% की कमी)

2018: 55

घाटी सिर्फ खूबसूरत नहीं, भरोसेमंद भी

पर्यटन

निवेश आकर्षित करने के लिए पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया।

- टूरिज्म और फिल्म नीति लागू की गई।

पर्यटक जम्मू-कश्मीर पहुंचे

(पर्यटक करोड़ में)

2024: 2.36

2023: 2.11

65,000 विदेशी पर्यटक शामिल

- वर्ष 2024 में 5.12 लाख श्रद्धालुओं ने अमरनाथ और 95.22 लाख ने श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा की।

14,488 बिस्तर की क्षमता वाले कुल 1,989 होम स्टे पंजीकृत किए गए हैं।

- 75 ऑफ-बीट स्थल और 75 नए एडवेंचर सर्किट अज्ञात क्षेत्रों में खोले गए हैं। 75 विरासत स्थल और 75 नए तीर्थयात्री/सूफी सर्किट की पहचान की गई है।
- पहली बार अक्टूबर 2024 में श्रीनगर में अंतरराष्ट्रीय मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें 12 देश शामिल हुए।

नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज की तस्वीरें देखकर तो हर भारतवासी गर्व से भर उठता है। नॉर्थ कश्मीर की गुरेज घाटी को पहली बार बिजली ग्रिड से जोड़ा गया है। कश्मीर में एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, हथकरघा उद्योग हो, स्पोर्ट्स हो या फिर स्टार्टअप, सभी के लिए अवसर बन रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट और स्पोर्ट्स का एक बड़ा हब बन रहा है। यहां खेती से जुड़े सेक्टर में करीब 70 स्टार्टअप बने हैं। बीते कुछ सालों में ही यहां 50 से ज्यादा डिग्री कॉलेज बने हैं। पॉलिटेक्निक में सीटें बढ़ने से यहां के नौजवानों को नया कौशल सीखने का मौका मिला है। आज जम्मू कश्मीर में आईआईटी, एम्स और अनेकों नए मेडिकल कॉलेज बने हैं। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में लोकल लेवल पर कुशल युवा तैयार किए जा रहे हैं। टूरिस्ट गाइड के लिए ऑनलाइन कोर्स हों या स्कूल-कॉलेज और यूनिवर्सिटी में

रोजगार

7.66 लाख स्वरोजगार/आजीविका के अवसर सृजित किए गए हैं वर्ष 2021-22 से अब तक।

39,466
अभ्यर्थी का चयन वर्ष 2019 से अब तक जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरी के लिए किया गया।

6,090
पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई है।

10,616
नए पद भर्ती एजेंसियों को भेजे गए हैं।

1,181
मामलों को अनुकंपा के तहत नियुक्ति के लिए मंजूरी दी गई।

7,376
पद के लिए विज्ञापन दिया गया।

युवा टूरिज्म क्लब की स्थापना, यह सभी काम आज कश्मीर में बहुत बड़े स्तर पर हो रहे हैं।

आकर्षण का केंद्र बन रहा जम्मू-कश्मीर-लद्दाख

विकास की शक्ति...पर्यटन की संभावनाएं...किसानों का सामर्थ्य... और जम्मू-कश्मीर के युवाओं का नेतृत्व...विकसित जम्मू-कश्मीर के निर्माण के मार्ग की ओर अग्रसर है। एक जमाना था जब

“पहले देश के लिए अधिकतर जो स्कीम बनती थी, जो कानून बनते थे, उनमें लिखा होता था-Except (एक्सेप्ट) J and K. (जम्मू-कश्मीर के अलावा) अब ये इतिहास की बात हो चुकी है। शांति और विकास के जिस मार्ग पर जम्मू और कश्मीर बढ़ रहा है, उसने राज्य में नए उद्योगों के आने का मार्ग भी बनाया है। आज जम्मू-कश्मीर आत्मनिर्भर भारत अभियान में अपना योगदान दे रहा है।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

गरीब कल्याण की योजनाएं पूरे देश में लागू होती थीं...लेकिन जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को उनका हक नहीं मिलता था। जब इरादे नेक हों, संकल्प को सिद्ध करने का जज्बा हो, तो फिर नतीजे भी मिलते हैं। कभी लोग कहते थे- जम्मू-कश्मीर में कौन पर्यटन के लिए जाएगा? लेकिन अब जम्मू-कश्मीर में पर्यटन के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अकेले 2024 में ही 2.3 करोड़ से ज्यादा पर्यटक यहां आए हैं। पिछले 10 वर्ष में अमरनाथ यात्रा में सबसे ज्यादा यात्री शामिल हुए। वैष्णो देवी में श्रद्धालु रिकॉर्ड संख्या में दर्शन कर रहे हैं। विदेशी टूरिस्ट की संख्या भी पहले से ढाई गुना बढ़ी है। अब बड़े-बड़े स्टार, सेलिब्रिटी, विदेशी मेहमान भी कश्मीर में आए बिना जाते नहीं हैं, वादियों में घूमने आते हैं, यहां वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं और यह वायरल हो रही हैं।

जम्मू-कश्मीर में पर्यटन के साथ ही कृषि और इससे जुड़े उत्पाद एक बड़ी पहचान रखते हैं। जम्मू-कश्मीर का केसर, सेब, मेवे और चेरी बड़े ब्रांड के तौर पर पहचाने जाते हैं। अब कृषि विकास कार्यक्रम से अगले 5 वर्ष में यहां के कृषि सेक्टर में अभूतपूर्व विकास होगा। विशेष तौर पर बागवानी और पशुधन के विकास में बहुत मदद मिलेगी। फल और सब्जियों को ज्यादा समय तक सुरक्षित रखने के लिए जम्मू-कश्मीर में स्टोरेज क्षमता भी काफी बढ़ाई गई है। कुछ दिन पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण स्कीम शुरू की गई है। इसके तहत जम्मू-कश्मीर में भी अनेक नए गोदाम बनाए जाएंगे।

सरकार सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी बहनों को टूरिज्म, आईटी और दूसरी स्किल की ट्रेनिंग देने का अभियान चला रही है। आज

जम्मू-कश्मीर में भी 1,200 से ज्यादा कृषि सखी काम कर रही हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत भी जम्मू-कश्मीर की बेटियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। टूरिज्म और स्पोर्ट्स में भारत दुनिया की एक बड़ी पावर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। इन दोनों सेक्टर में जम्मू कश्मीर के पास बहुत सामर्थ्य है। आज जम्मू-कश्मीर के हर जिले में शानदार स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। यहां खेलो इंडिया के करीब 100 सेंटर बनाए जा रहे हैं। जम्मू-कश्मीर के करीब साढ़े 4 हजार नौजवानों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। विंटर स्पोर्ट्स के मामले में तो प्रदेश एक प्रकार से भारत का कैपिटल बनता जा रहा है।

जम्मू-कश्मीर आज तेज रफ्तार से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। यहां के लोगों को एक नहीं, बल्कि 2-2 एम्स की सुविधा मिलने जा रही है। एम्स जम्मू का उद्घाटन हो चुका है और एम्स कश्मीर पर तेजी से काम चल रहा है। 7 नए मेडिकल कॉलेज, 2 बड़े कैंसर अस्पताल स्थापित किए गए हैं। आईआईटी और आईआईएम जैसे आधुनिक शिक्षा संस्थान भी बने हैं। जम्मू-कश्मीर में 2 वंदे भारत ट्रेन भी चल रही हैं। श्रीनगर से संगलदान और संगलदान से बारामूला के लिए ट्रेन सेवा शुरू हो चुकी है। कनेक्टिविटी के विस्तार से जम्मू-कश्मीर में आर्थिक गतिविधियां तेज हुई हैं। जम्मू और श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के नए प्रोजेक्ट भी लाए जा रहे हैं। आने वाले समय में जम्मू-कश्मीर की विकास गाथा पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र बनेगी।

एक देश-एक संविधान का संकल्प भी साकार

अक्टूबर, 2024 में जम्मू-कश्मीर ने एक और इतिहास रचा। अनुच्छेद 370 और 35ए के निष्प्रभावी होने और राज्य पुनर्गठन के बाद यहां पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए। आजादी के बाद यह पहली बार हुआ कि विधानसभा चुनाव के बाद किसी मुख्यमंत्री ने भारतीय संविधान के नाम पर पद व गोपनीयता की शपथ ली। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, "आज देश का हर नागरिक खुश है कि आजादी के सात दशक बाद एक देश, एक संविधान का संकल्प पूरा हुआ है, सरदार साहब की आत्मा को मेरी ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। देशवासियों को पता नहीं है 70 साल तक बाबा साहब अंबेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था।" पहली बार राज्य विधानसभा चुनाव में बिना भेदभाव के वोट डाले गए। आजादी के सात दशक बाद भी अनेक लोग वोट डालने के अधिकार से वंचित थे। उन्होंने भी पहली बार इस चुनाव में अपना वोट डाला है। अनुच्छेद 370 को लंबे समय तक राजनीति का हथियार बनाया गया, इससे यहां के लोगों के अधिकार छीन लिए थे, भारत का संविधान जम्मू-कश्मीर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता था। अब अनुच्छेद 370 की दीवार गिर चुकी है। पत्थरबाजी बंद है, लोकतंत्र मजबूत है। लोग भारत के संविधान, भारत के तिरंगे झंडे और भारत के लोकतंत्र में भरोसा करते हुए बढ़-चढ़ कर मतदान करने के लिए आगे आ रहे हैं। 1947 के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में बीडीसी के चुनाव कराए गए। आज पहली बार प्रशासन के हर स्तर पर, फिर चाहे वो विधायक हों, बीडीसी

हमने संविधान संशोधन देश की एकता के लिए किए। बाबा साहब अंबेडकर का संविधान 370 की दीवार के कारण जम्मू-कश्मीर की तरफ देख भी नहीं सकता था। हम चाहते थे संविधान हिंदुस्तान के हर हिस्से में लागू होना चाहिए और इसलिए बाबा साहब को श्रद्धांजलि भी देनी थी, देश की एकता को मजबूत करना था, हमने संविधान संशोधन किया, डंके की चोट पर किया। अनुच्छेद 370 को हटाया तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मुहर लगा दी।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

जम्मू... ऐसा पहला शहर जहां है आईआईटी, आईआईएम और एम्स

स्वास्थ्य

- जम्मू के विजयपुर में एम्स का उद्घाटन।
- 100-100 बिस्तर वाले बालटाल और चंदनवारी में डीआरडीओ द्वारा अस्पताल का निर्माण।
- राज्य में दो नए कैंसर संस्थान स्वीकृत और उन्हें शुरू भी किया गया।

1,828 करोड़ रुपये की लागत से अवंतीपुरा में एम्स का निर्माण प्रगति पर।

10 सरकारी मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की गई।

800 एमबीबीएस और 297 पीजी सीट 2019 के बाद जोड़ी गई।

3,104 वेलनेस सेंटर के अलावा 270 जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए।

372 डीएनबी सीट स्वीकृत की गई।

1,690 सीट पैरामेडिकल में जोड़ी गईं।

बढ़ी मेडिकल की सीटें

49 बीएससी नर्सिंग कॉलेज बढ़े।

19 बीएससी पैरामेडिकल कॉलेज जोड़े गए।

2,305 नर्सिंग सीट जोड़ी गई।

208 सीट एमएससी नर्सिंग में जोड़ी गई।

शिक्षा

- जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरी तरह से लागू की गई।
- 3 इंजीनियरिंग कॉलेज सहित 51 नए कॉलेज बनाए गए। 600 अतिरिक्त सीट पॉलिटेक्निक की जोड़ी गईं।
- 396 स्कूलों को पीएम श्री योजना के तहत चरण-I, II और III में अपग्रेडेशन की मंजूरी दी गई ।
- 46 हजार बच्चे जो स्कूल से बाहर थे उन्हें मुख्यधारा में लाया गया। साथ ही, 9वीं से 12वीं तक के 1.21 लाख छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम में पंजीकृत किया गया।

हों, डीडीसी हों, अब जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि काम कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में संविधान की भावना और उसकी मर्यादा की पुनर्प्रतिष्ठा हुई है, जो बाबा साहब अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि है।

विश्वास बहाली के साथ विकास

जम्मू-कश्मीर का विकास सुनिश्चित करना है तो सबसे पहले आवाम को भरोसे में लेना होगा और उस पर भरोसा भी करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सोच को उपराज्यपाल द्वारा लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। 'मुलाकात' 'बैक टू विलेज' योजना के जरिए आम लोगों से फीडबैक लेना, पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाना इसमें बेहद कारगर साबित हुआ है। जम्मू-कश्मीर-लद्दाख के इतिहास में पहली बार ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में 98 फीसदी से अधिक वोटिंग इसका परिचायक है। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को लाकर लोगों की आकांक्षाओं को नया अवसर दिया जा रहा है, ताकि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की अपनी महान विरासत को सशक्त किया जा सके।

नया लद्दाख, नई शुरूआत

अनुच्छेद 370 के बाद विकास की रफ्तार

- लेह में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) द्वारा 50 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कार्य शुरू।
- केंद्र शासित लद्दाख द्वारा ई-वाहन नीति अधिसूचित की गई।

19,755 सोलर वाटर हीटर वितरित किए गए पिछले चार वर्ष में। इससे प्रति वर्ष 36 किलो टन कार्बन उत्सर्जन कम हुआ।

72 सौर लिफ्ट सिंचाई पंप लगाए गए लद्दाख के सूखाग्रस्त क्षेत्र में।

5,25,374
पर्यटक रिकॉर्ड वर्ष 2023 में लद्दाख आए।

- 2 टूरिस्ट सर्किट, 9 टूरिस्ट रूट व 30 ट्रैकिंग रूट खोले गए।
- कारगिल में 170 बिस्तर के अस्पताल का निर्माण, अस्पताल शुरू।

100%
आबादी आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत कवर।

- लेह में मेडिकल और कारगिल में इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू किए जाने का प्रस्ताव।

17,500
टैबलेट, कक्षा छह से 12वीं तक के छात्रों को दिया गया ताकि वे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें।

- 40 एस्ट्रोनॉमी लैब, 24 अटल टिंकरिंग और रोबोटिक लैब की स्थापना उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में की गई।
- 25 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी के साथ सिंधु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। यह औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा।

640 करोड़ रु. की लागत से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से लेह में आधुनिक एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है।

महिलाओं और बच्चों को अधिकार वापस मिले हैं जो पहले राज्य से बाहर शादी करने पर छिन जाते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी नए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कदम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लंबे समय से अटकी परियोजनाओं में तेजी आई है तो चिनाब पर बन रहा दुनिया का सबसे ऊंचा और बेहतरीन रेलवे ब्रिज हर भारतीय को गौरवान्वित कर रहा है। किसी भी राष्ट्र में कनेक्टिविटी जब बेहतर होती है तो इससे पर्यटन और उद्योग दोनों को बल मिलता है। कालीन से लेकर केसर तक, सेब से लेकर बासमती चावल तक जम्मू-कश्मीर की महक पूरे देश में फैल रही है। नए कृषि सुधारों ने जम्मू और घाटी, दोनों जगह फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए नए अवसर बना दिए हैं। इससे हजारों लोगों को रोजगार और स्वरोजगार का अवसर मिल रहा है। जम्मू-कश्मीर-लद्दाख में जहां

60,793 स्मार्ट बिजली मीटर लद्दाख में अभी तक लगाए गए हैं।

44 नए पुल का निर्माण किया गया है।

309 मोबाइल टावर की स्थापना और 297 4जी टावर लगाने की मंजूरी लद्दाख के केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद दी गई।

550 किलोवाट क्षमता की एक मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट की स्थापना कारगिल और लेह में की गई।

- श्रीनगर-लेह 220 केवी ट्रांसमिशन लाइन का काम प्रधानमंत्री विकास पैकेज-2015 के तहत पूरा किया गया।

1,000 मीट्रिक टन क्षमता की कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की गई।

3,172 पद को भरा गया लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद। इसमें 234 महिला पुलिस की भर्ती की गई।

3,818 पॉलीकार्बोनेट ग्रीन हाउस स्थापित किए गए हैं, जिसे 'लद्दाख ग्रीन हाउस' के रूप में जाना जाता है। पॉलीकार्बोनेट ग्रीन हाउस से सर्दियों के दौरान सब्जियों के उत्पादन में मदद मिली है।

> **आज जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों के सपने बीते समय के मोहताज नहीं, बल्कि भविष्य की संभावनाएं हैं। जम्मू और कश्मीर में मोहभंग, निराशा और हताशा की जगह अब विकास, लोकतंत्र और गरिमा ने ले ली है।**
>
> **-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

एक तरफ हजारों सरकारी नौकरियां नोटिफाई की जा रही हैं। दूसरी ओर बैंकों के जरिए अब जम्मू कश्मीर के नौजवान कारोबारियों को आसानी से लोन मिलना शुरू हुआ है। लद्दाख में बौद्ध अध्ययन केंद्र के साथ पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय की योजना को आकार दिया जा रहा है। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिए जाने की लंबे समय से लंबित मांग को भी पूरा किया गया है।

जब अनुच्छेद 370 पर लगी 'सुप्रीम' मुहर

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 और 35(ए) को निरस्त करने पर 11 दिसंबर 2023 को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में भारत की संप्रभुता और अखंडता को बरकरार रखा है, जिसे प्रत्येक भारतीय द्वारा सदैव संजोया जाता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा

नई नीति से आसान हुई राह

उद्योग

- जम्मू-कश्मीर औद्योगिक नीति (2021-30)
- जम्मू-कश्मीर भूमि आवंटन नीति (2021-30)
- जम्मू-कश्मीर निजी औद्योगिक संपदा विकास नीति (2021-30)
- नई स्टार्टअप नीति (2024-27)

1,63,831 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश के साथ 8,293 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें 5.89 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद।

1,030 स्टार्टअप डीपीआईआईटी के साथ पंजीकृत। इनमें 380 का नेतृत्व महिला कर रही हैं।

उद्योग को आकर्षित करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए 46 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं।

- वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रथम राष्ट्रीय ओडीओपी पुरस्कारों में श्रेणी बी राज्यों में जम्मू-कश्मीर को प्रथम स्थान (स्वर्ण) मिला।
- इस साल जून में श्रीनगर विश्व शिल्प परिषद (डब्ल्यूसीसी) द्वारा 'विश्व शिल्प शहर' के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बना।

किसान

12.80 लाख किसान के बैंक खातों में 3,676 करोड़ रुपये किसान सम्मान निधि के भेजे गए।

- पीएम फसल बीमा योजना का विस्तार सभी जिलों तक किया गया।
- 17 मंडी को ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया। अब तक 55,029 किसान/एफपीओ/सहकारी समिति पंजीकृत।

16.94 लाख क्विंटल (1,044 करोड़ रुपये) का कारोबार इन मंडियों से अब तक हुआ है।

कि 5 अगस्त 2019 को लिया गया निर्णय संवैधानिक एकीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया था न कि इसका उद्देश्य विघटन था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को भी भली-भांति माना है कि अनुच्छेद 370 का स्वरूप स्थायी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 2023 के अपने निर्णय में 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को मजबूत किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जीवन के शुरुआती दौर से ही जम्मू-कश्मीर आंदोलन से जुड़े रहे हैं। उनकी अवधारणा सदैव ही ऐसी रही है जिसके अनुसार जम्मू-कश्मीर महज एक राजनीतिक मुद्दा नहीं था, बल्कि यह विषय समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने के बारे में था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आलेख लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, "डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नेहरू मंत्रिमंडल में एक महत्वपूर्ण विभाग मिला हुआ था और वे काफी लंबे समय तक सरकार में बने रह सकते थे। फिर भी, उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर मंत्रिमंडल छोड़ दिया और आगे का कठिन रास्ता चुना, भले ही इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। लेकिन उनके अथक प्रयास और बलिदान से करोड़ों भारतीय कश्मीर मुद्दे से भावनात्मक रूप से जुड़ गए। कई वर्षों बाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने श्रीनगर में एक सार्वजनिक बैठक में 'इंसानियत', 'जम्हूरियत' और 'कश्मीरियत' का प्रभावशाली संदेश दिया, जो सदैव ही प्रेरणा का महान स्रोत भी रहा है।"

इस आलेख में उन्होंने लिखा कि अनुच्छेद 370 और 35(ए) जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सामने बड़ी बाधाओं की तरह थे। ये अनुच्छेद एक अटूट दीवार की तरह थे और गरीब, वंचित, दलित-पिछड़े एवं महिलाओं के लिए पीड़ादायक थे। अनुच्छेद 370 और 35(ए) के कारण जम्मू-कश्मीर के लोगों को वह अधिकार और विकास कभी नहीं मिल पाया, जो उनके साथी देशवासियों को मिले। इन अनुच्छेदों के कारण, एक ही राष्ट्र के लोगों के बीच दूरियां पैदा हो गईं। इस दूरी के कारण, हमारे देश के कई लोग, जो जम्मू-कश्मीर की समस्याओं को हल करने के लिए काम करना चाहते थे, ऐसा करने में असमर्थ थे, भले ही उन लोगों ने वहां के लोगों के दर्द को स्पष्ट रूप से महसूस किया हो। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आलेख में इस बात पर जोर दिया कि जम्मू-कश्मीर के लोगों की सेवा करते समय, केंद्र सरकार ने तीन बातों को प्रमुखता दी-नागरिकों की चिंताओं को समझना, सरकार के कार्यों के माध्यम से आपसी-विश्वास का निर्माण करना तथा विकास, निरंतर विकास को प्राथमिकता देना। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं ने शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है, ऐसी योजनाओं में समाज के

> जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब तक 9 टूरिस्ट रूट, 2 नए टूरिस्ट सर्किट व 30 ट्रैकिंग रूट तथा लद्दाख के हनले गांव में विदेशी पर्यटकों के लिए रात्रि विश्राम की अनुमति दी गई है।

सभी वर्गों को शामिल किया गया है। इनमें सौभाग्य और उज्ज्वला योजना शामिल हैं।

आवास, नल से जल कनेक्शन और वित्तीय समावेशन में प्रगति हुई है। लोगों के लिए बड़ी चुनौती रहे स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भी बुनियादी ढांचे का विकास किया गया है। सभी गांव ने खुले में शौच से मुक्त-ओडीएफ प्लस का दर्जा प्राप्त कर लिया है। सरकारी रिक्तियां, जो कभी भ्रष्टाचार और पक्षपात का शिकार होती थीं, पारदर्शी और सही प्रक्रिया के तहत भरी गई हैं। शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) जैसे अन्य संकेतकों में सुधार दिखा है। बुनियादी ढांचे और पर्यटन में बढ़ावा सभी देख सकते हैं। इसका श्रेय स्वाभाविक रूप से जम्मू-कश्मीर के लोगों की दृढ़ता को जाता है, जिन्होंने बार-बार दिखाया है कि वे केवल विकास चाहते हैं और इस सकारात्मक बदलाव के वाहक बनने के इच्छुक हैं। अब रिकॉर्ड वृद्धि, रिकॉर्ड विकास, पर्यटकों के रिकॉर्ड आगमन के बारे में सुनकर लोगों को सुखद आश्चर्य होता है।

इतना ही नहीं, जब भी आस-पड़ोस की नापाक शक्तियों की गिद्ध दृष्टि ने जम्मू-कश्मीर की शांति को भंग करने की कोशिश की, केंद्र सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक कदम उठाकर माकूल जवाब दिया है। उरी सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर इसका परिचायक है।

निश्चित रूप से कोई भी परिवर्तन तब होता है, जब परिवर्तन करने का दिल में लगाव हो। अगर कोई सत्ता भोगने के लिए आता है तो वो परिवर्तन नहीं कर सकता है। लोगों के सुख-दुख और प्रगति के साथ अगर मन से जुड़ाव होता है तो परिवर्तन होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में लोकतंत्र के प्रति लगाव है। इसी लगाव के कारण यहां परिवर्तन आया है। ऐसे में नए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की प्रगति की गति केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संसद में दिए गए वक्तव्य को अक्षरशः सही साबित कर रहा है कि अनुच्छेद 370 एक ऐतिहासिक भूल थी, जिसे 5 अगस्त 2019 को ठीक कर राष्ट्र का सही मायने में एकीकरण किया गया। ▪

देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास

सहकार बेहतर कल का शक्तिशाली आधार

भारत एक ऐसा देश है जहां विकास की गूंज खेत, गांव और शहर में एक साथ सुनाई देती है। सहकारिता इस विकास का एक मौन लेकिन शक्तिशाली आधार है। किसान को उचित मूल्य की बात हो या फिर महिला एवं छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाना, भारत में सहकारी समितियां आर्थिक, मानवीय और पर्यावरण समृद्धि के साथ गरीब कल्याण के समावेशी विकास का ताना-बाना बुन रही हैं। सहकारिता को और मजबूती देने की कड़ी में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 5 जुलाई को गुजरात के आणंद में किया देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास...

सहकारी समितियां जन-केंद्रित होती हैं जिनका स्वामित्व, नियंत्रण और संचालन उसके सदस्य ही करते हैं। वे अपनी सामान्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकता और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं। स्वतंत्रता पूर्व एक छोटी सी यात्रा के रूप में शुरू हुई सहकारिता आज पूरे भारत में 8.42 लाख सहकारी समिति के नेटवर्क के साथ जन आंदोलन का रूप ले चुकी है, जिसमें देश का हर चौथ नागरिक जुड़ा है। वहीं, वैश्विक स्तर पर इनकी संख्या 30 लाख है। देश के करोड़ों गरीब और ग्रामीणों के जीवन में आशा का संचार कर उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए 4 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की थी। सहकारिता के वैश्विक महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है।

वैश्विक महत्व वाली सहकारिता को देश में और मजबूती देने के लिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के आणंद में देश के पहले त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का भूमि पूजन किया। 500 करोड़ रुपये की लागत से यह 125 एकड़ में बनाया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय

सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि इसके बाद से भारत में सहकारिता क्षेत्र के विकास और संवर्धन के लिए 60 नई पहल की गई हैं। सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने में जो कमियां रह गईं थीं, यह विश्वविद्यालय उन्हें पूरा करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज देशभर में सहकारिता आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास इसी दिशा में एक युगांतरकारी कदम है।

सहकारिता के कर्मचारियों और सहकारी समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण की अभी कोई सुचारू व्यवस्था नहीं है। लिहाजा कोऑपरेटिव में भर्ती के बाद कर्मचारी को ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन अब यूनिवर्सिटी बनने के बाद उसी को नौकरी मिलेगी जिन्होंने प्रशिक्षण लिया होगा। इसके बाद सहकारिता में और पारदर्शिता आएगी। ■

देश में सहकारिता की पहचान अमूल के संस्थापक अध्यक्ष पर रखा नाम

त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का नाम त्रिभुवन दास किशिभाई पटेल के नाम पर रखा गया है। त्रिभुवन दास वह व्यक्ति थे जिन्होंने सरदार वल्लभभाई पटेल के मार्गदर्शन

में गुजरात में आणंद की भूमि पर एक नए विचार का बीज बोने का काम किया था। पॉलसन डेयरी की शोषणकारी नीति के सामने उन्होंने दूध इकट्ठा करने की एक छोटी सी मंडली बनाई। उन्होंने गुजरात राज्य सहकारी दुग्ध विपणन संघ की स्थापना की, जिसे आज अमूल के नाम से जाना जाता है। त्रिभुवन दास इसके पहले संस्थापक अध्यक्ष बने। 1946 में खेड़ा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ की स्थापना हुई जिसमें आज 36 लाख बहनें 80 हजार करोड़ रुपये का कारोबार करती हैं।

कोऑपरेटिव विकास रणनीति बनाने का काम करेगी यूनिवर्सिटी

- यूनिवर्सिटी सहकारिता में नीति निर्माण, डेटा विश्लेषण और कोऑपरेटिव के विकास की 5, 10 और 25 साल तक की रणनीति बनाने का काम करेगी।
- युवाओं को तकनीकी विशेषज्ञता, अकाउंटेंसी, वैज्ञानिक अप्रोच के साथ सहकारिता के संस्कार भी सीखने को मिलेंगे।

साल के अंत तक बन जाएंगे 60 हजार नए पैक्स

- देश में 2 लाख नए प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) बनाने का निर्णय लिया गया है जिनमें से 60 हजार नए पैक्स इस वर्ष के अंत तक बन जाएंगे।
- 2 लाख पैक्स में ही 17 लाख कर्मचारी होंगे।
- सीबीएसई ने 9 से 12 कक्षा के पाठ्यक्रम में सहकारिता विषय को जोड़ा है।

“ देश में सहकारिता हमारे समाज के संस्कार के रूप में वैदिक काल से चली आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ‘सहकार से समृद्धि’ के मूल मंत्र से देश के सहकारी तंत्र को नई गति दे रहे हैं।

– अमित शाह, गृह एवं सहकारिता मंत्री

गृह एवं सहकारिता मंत्री ने किया ‘सहकार संवाद’

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में 9 जुलाई को अहमदाबाद में गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सहकारिता क्षेत्र से जुड़ी माताओं-बहनों व अन्य कार्यकर्ताओं के साथ ‘सहकार संवाद’ किया। इस संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि मैंने तय किया है कि मैं जब भी सेवानिवृत्त हो जाऊंगा तो मैं बाकी का जीवन वेद, उपनिषद और प्राकृतिक खेती के लिए इस्तेमाल करुंगा। प्राकृतिक खेती, एक वैज्ञानिक प्रयोग है जिसके कई प्रकार के फायदे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने खेतों में प्राकृतिक खेती अपनाई है और उत्पादन में लगभग डेढ़ गुना की बढ़ोतरी हुई है।

डिजिटल स्वास्थ्य पहचान के साथ स्वस्थ भारत की नींव

भारत जैसे 140 करोड़ से ज्यादा आबादी और भौगोलिक कठिनाइयों वाले विशाल देश में स्वास्थ्य सेवाओं तक सबकी आसान पहुंच कैसे हो? तकनीक के इस युग में भारत ने स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल व्यवस्था के साथ जोड़कर न सिर्फ इसका हल निकाला, बल्कि करोड़ों नागरिकों तक इसे पहुंचाकर अपने सामर्थ्य और दक्षता प्रमाण भी दिया। 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के साथ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तौर पर शुरू हुआ स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटलीकरण का यह दौर अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ बना है ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रतीक...

दिल्ली के द्वारका में रहने वाली अफसाना आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (एबीएचए यानी आभा) की खूबियां गिनाते हुए कहती हैं, "अब न तो अपनी मेडिकल रिपोर्ट साथ रखनी पड़ती है और न जांच रिपोर्ट खोने का डर है। एक क्लिक पर डॉक्टर को सब दिख जाता है।"

आभा का ऐसा ही कुछ अनुभव प्रिया राघव का भी है। प्रिया कहती हैं, "इससे काफी समय बचता है। इसलिए सभी को यह कार्ड बनवाना चाहिए।"

यह कहानी सिर्फ अफसाना और प्रिया की नहीं है, बल्कि करोड़ों ऐसे लोगों की भी है, जिनको आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) का लाभ मिल रहा है।

कोविड महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया थमी हुई थी, तब डिजटल तकनीक के महत्व को सबने बहुत करीब से जाना। कोविन एप जैसी सेवाओं ने भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं में परिवर्तन के एक नए युग की शुरुआत की। सबको मुफ्त वैक्सीन अभियान के तहत भारत ने कोविन एप के जरिए ही दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान संभव कर दिखाया। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत ने स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण के नए युग का सूत्रपात किया। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सफल क्रियान्वयन के बाद इसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के रूप में पूरे देश में शुरू किया गया। अब डिजिटल स्वास्थ्य सेवा की यह क्रांति न केवल बड़े शहरों की आधुनिक सुविधाओं को और प्रभावी बना रही है, बल्कि दूरदराज के गांवों में भी स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सरल, पारदर्शी और भरोसेमंद बना रही है। इस मिशन के माध्यम से विशिष्ट स्वास्थ्य आईडी के जरिए, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और रोगियों

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के महत्वपूर्ण अंग

1. **आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (आभा):** एक 14 अंक की यूनिक संख्या है, जो तमाम स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में सहेज कर रखती है।
2. **हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री (एचपीआर)** पंजीकृत हेल्थकेयर पेशेवरों का एक व्यापक डेटाबेस।
3. **स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री (एचएफआर):** पूरे भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं का एक डिजिटल भंडार।
4. **एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस (यूएचआई):** डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा प्रदान करने वाला एक ओपन नेटवर्क। इसके माध्यम से अस्पताल, डॉक्टर, प्रयोगशाला सभी एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध।
5. **यू-विन:** टीकाकरण वितरण में दक्षता और जवाबदेही को और बढ़ाने के लिए सरकार ने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम (यूआईपी) के तहत एक डिजिटल पहल, यू-विन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। यू-विन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो गर्भवती महिलाओं और बच्चों (0-16 वर्ष) के लिए टीकाकरण को व्यवस्थित बनाने के साथ ट्रैक भी करता है।

राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई-संजीवनी

निशुल्क और दूरस्थ चिकित्सा परामर्श प्रदान करती है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए दुनिया के सबसे बड़े टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म के रूप में उभर रही है। ई-संजीवनी ने 2020 में अपनी शुरुआत के बाद से टेली कंसल्टेशन के माध्यम से 36 करोड़ से अधिक रोगियों की सेवा की है। ई-संजीवनी के तहत 130 स्पेशियलिटी के डॉक्टर तो साथ ही 2,32,291 स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को जोड़ा गया है।

- 10.48 करोड़ लाभार्थी मई 2025 तक यू-विन पर पंजीकृत हुए हैं। इसमें 93.91 लाख प्रसव, 1.88 करोड़ टीकाकरण सत्र और 41.73 करोड़ वैक्सीन खुराक की सुविधा शामिल है।

नोट : आंकड़े 6 अप्रैल 2025 तक के।

" देश के स्वास्थ्य सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमने एक नेशनल अप्रोच, एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पर काम किया। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर आयुष्मान भारत और अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन तक, ऐसे अनेक प्रयास इसी का हिस्सा हैं।

– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

सफलता की कहानी, आंकड़ों की जुबानी

79 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते (आभा) बने।

4.14 लाख से अधिक सत्यापित स्वास्थ्य सुविधाएं पंजीकृत, इसमें अस्पताल, क्लीनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर शामिल।

6.65 लाख से अधिक सत्यापित स्वास्थ्य पेशेवर पंजीकृत।

61 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड जुड़े हैं।

नोट : आंकड़े 9 जुलाई 2025 तक के।

आप ऐसे बना सकते हैं आभा

- आभा कार्ड बनवाने के लिए आपको आभा कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट **https://abha.abdm.gov.in/abha/v3/** पर जाना होगा।
- इसके बाद 'आभा नंबर बनाएं' पर क्लिक करें। फिर 'अपना आभा नंबर बनाएं आधार से', या 'ड्राइविंग लाइसेंस से' का विकल्प मिलेगा।
- आप आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी चुनेंगे उसके बाद आपको अपना ब्यौरा देना होगा।

को एकीकृत करके एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। योजना के तहत, प्रत्येक भारतीय को स्वास्थ्य आईडी दी जाती है। इस स्वास्थ्य खाते में हर जांच, हर बीमारी, डॉक्टरों से मिलने, ली गई दवाओं और निदान का विवरण होता है। भले ही मरीज नई जगह शिफ्ट हो जाए या किसी नए डॉक्टर से मिले, उसे सिर्फ आभा (यूनिक नंबर) बताना होता है। वहीं, टेलीमेडिसिन ई-संजीवनी के जरिए कोई भी घर बैठे ही डॉक्टर से संपर्क कर परामर्श ले सकता है।

देश की स्वास्थ्य सेवाओं में इस नीतिगत सुधार और डिजिटल बदलाव के दौर का जिक्र करते हुए वर्ल्ड इकॉनमिक फोरम ने भी अपनी एक रिपोर्ट में भारत को डिजिटल स्वास्थ्य में एक वैश्विक पथप्रदर्शक बताया है।

BRICS
BRICS Brasil 2025

ब्रिक्स के शिखर पर भारत

आज जब विश्व व्यवस्थाओं पर चारों तरफ से दबाव है और दुनिया अनेक चुनौतियों से जूझ रही है। ऐसे समय में भारत की भूमिका और उसकी रीति-नीति की झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2-9 जुलाई तक ग्लोबल साउथ के 5 अहम देश के दौरे पर दिखाई दी। घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना और नामीबिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ के देशों को उचित प्रतिनिधित्व पर जोर दिया। वहीं, ब्राजील में ब्रिक्स के 17वें शिखर सम्मेलन के मंच पर तमाम विरोधाभास को दरकिनार कर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जैसे मुद्दे समेत भारत की प्राथमिकताएं रियो डी जेनेरियो घोषणापत्र में हुईं शामिल...

वैश्विक शांति और सुरक्षा केवल एक आदर्श नहीं है, ये सभी के साझा हित और भविष्य की बुनियाद है। एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में ही मानवता का विकास संभव है। ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया से लेकर यूरोप तक विश्व विवाद और तनावों से घिरा हुआ है, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम मुद्दों को उठाया।

ब्रिक्स सम्मेलन के चार सत्र के संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद से लेकर वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म्स और ग्लोबल साउथ के देशों के साथ दोहरे व्यवहार का जिक्र किया। पढ़िए किस मुद्दे पर क्या बोले प्रधानमंत्री मोदी...

आतंकवाद पर सख्ती की मांग

- शांति और सुरक्षा पर आयोजित सत्र में कश्मीर घाटी के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए कायराना आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद आज मानवता के लिए सबसे गंभीर चुनौती बनकर खड़ा है।
- भारत ने भी पहलगाम में एक अमानवीय और कायरतापूर्ण आतंकी हमले का सामना किया। आतंकवाद की निंदा हमारा 'सिद्धांत' होना चाहिए, केवल 'सुविधा' नहीं।
- आतंकवादियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने पर कोई संकोच नहीं होना चाहिए। आतंकवाद के पीड़ित और समर्थकों को एक ही तराजू में नहीं तौल सकते।

असर भारत की पहल पर ब्रिक्स देशों ने 31 पेज और 126 बिंदुओं के अपने संयुक्त घोषणापत्र में पहलगाम हमले की निंदा करते हुए आतंकवाद को सैद्धांतिक रूप से खारिज करने की बात कही।

ग्लोबल साउथ के साथ भेदभाव...

- वैश्विक शासन पर आयोजित ब्रिक्स सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ अक्सर दोहरे मापदंड का शिकार रहा है।
- चाहे विकास की बात हो, संसाधनों का वितरण हो या सुरक्षा से जुड़े विषय, ग्लोबल साउथ के हितों को प्राथमिकता नहीं मिली है।
- क्लाइमेट फाइनेंस, सतत विकास और प्रौद्योगिकी तक पहुंच जैसे विषयों पर ग्लोबल साउथ को अक्सर सांकेतिक मदद के अलावा कुछ नहीं मिला।

वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म्स पर...

- प्रधानमंत्री मोदी ने 20वीं सदी में स्थापित वैश्विक संस्थाओं में 21वीं सदी के हिसाब से बदलाव का मुद्दा उठाते हुए कहा कि ग्लोबल संस्थानों में मानवता के दो-तिहाई हिस्से को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है।
- जिन देशों का आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है, उन्हें डिसीजन मेकिंग टेबल पर नहीं बिठाया गया। यह केवल प्रतिनिधित्व नहीं, बल्कि विश्वसनीयता और प्रभावशीलता का भी प्रश्न है। बिना ग्लोबल साउथ के ये संस्थाएं मोबाइल में बिना नेटवर्क की सिम की तरह हैं।

अरर प्रधानमंत्री मोदी के उठाए इस मुद्दे का ब्रिक्स घोषणा पत्र में समर्थन करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार का समर्थन किया। ब्रिक्स देशों ने उन एकतरफा प्रतिबंधों की निंदा की जो अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के खिलाफ हैं।

तकनीक के नियमन पर जोर...

- स्ट्रेथनिंग मल्टीलेटरलिज्म, आर्थिक-वित्तीय मामलों और एआई पर आयोजित सत्र में ब्रिक्स के बढ़ते महत्व का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने चार सुझाव दिए।
- पहला, ब्रिक्स की ओर से स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक को सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना चाहिए जो जरूरी हों, लंबे समय तक फायदे वाले हों और जिससे बैंक की साख बनी रहे।
- दूसरा, ऐसा ब्रिक्स रिसर्च सेंटर बनाया जाए, जहां सब देश मिलकर काम कर सकें।
- तीसरा, क्रिटिकल मिनरल्स और टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाते हुए इनकी सप्लाई चेन को सुरक्षित और लचीला बनाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। कोई भी देश इनका उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए या हथियार के रूप में न करे।
- चौथा, ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे पता चले कि कोई डिजिटल जानकारी असली है या नहीं, वो कहां से आई और उसका गलत इस्तेमाल न हो।

पर्यावरण पर भारत के प्रयासों का जिक्र...

- पर्यावरण, कॉप-30 और वैश्विक स्वास्थ्य पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इसे लेकर भारत की सोच व संस्कृति के साथ पर्यावरणीय लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का जिक्र किया।
- भारतीय सभ्यता और संस्कृति में, पृथ्वी को मां का दर्जा दिया गया है। इसीलिए जब पृथ्वी मां पुकारती है, तो हम चुप नहीं रहते। हम अपनी सोच, अपने व्यवहार और अपनी जीवनशैली में बदलाव करते हैं।
- पीएम मोदी ने भारत की ओर से इस दिशा में किए गए प्रयासों जैसे, लाइफ स्टाइल फॉर एन्वॉयरमेंट, इंटरनेशल सोलर अलायंस, एक पेड़ मां के नाम, आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन, ग्रीन हाईड्रोजन मिशन और इंटरनेशल बिग कैट अलायंस का भी जिक्र किया।
- सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत पेरिस कमिटमेंट को पूरा करने वाला पहला देश है।

अरर पहली बार ब्रिक्स एजेंडे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस को प्रमुखता दी गई है। इस विषय पर ब्रिक्स नेताओं का बयान जारी कर कहा गया कि एआई गवर्नेंस के लिए एक सामूहिक वैश्विक प्रयास की आवश्यकता है। इसका उद्देश्य एआई तकनीकों के जिम्मेदार विकास, तैनाती और उपयोग को बढ़ावा देना है, जो हर देश के नियम-कानून एवं संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप हो।

अरर भारत की बिग कैट अलायंस जैसी पहलों का स्वागत करते हुए घोषणापत्र में विकासशील देशों के लिये संसाधन जुटाने हेतु जलवायु वित्त जैसे मुद्दों को शामिल किया गया। "ब्रिक्स लीडर्स फ्रेमवर्क डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट फाइनेंस" को अपनाया गया। इसका उद्देश्य विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त को सुलभ, समय पर और किफायती बनाना है, ताकि वे न्यायसंगत तरीके से हरित विकास की ओर बढ़ सकें।

दुनिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ब्रिक्स...

- ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने अपने नाम के पहले अक्षरों के साथ BRIC संगठन की स्थापना की थी।
- 2010 में दक्षिण अफ्रीका के जुड़ने के बाद यह BRICS हो गया। भारत वर्ष 2026 में एक बार फिर ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालेगा।
- ब्रिक्स देशों में दुनिया की 45% जनसंख्या है। यह वैश्विक जीडीपी में 37.3% हिस्सेदारी रखता है, जो यूरोपीय संघ के 14.5% और जी-7 के 29.3% से अधिक है।
- ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिक्स में शामिल होने के साथ ब्रिक्स अब वैश्विक कच्चे तेल उत्पादन का लगभग 44% हिस्सा रखता है।

पीएम मोदी का विदेश दौरा

भारत की आवाज अब ग्लोबल साउथ की ताकत...

आर्थिक और सामाजिक विकास के आधार पर दुनिया को साउथ और नॉर्थ में बांटना उपनिवेशवाद की देन है। यह आश्चर्य ही है कि दुनिया की करीब 40 फीसदी जीडीपी, करीब 85 फीसदी आबादी और वैश्विक कारोबार में 40 फीसदी से अधिक का हिस्सा रखने वाले ग्लोबल साउथ के 100 से ज्यादा देशों को लंबे समय से असमानता झेलनी पड़ी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ नई भू-राजनीतिक व्यवस्था में भारत ने अपने उदय और बढ़ते प्रभाव के बीच इन देशों को नया मंच देकर उनकी आवाज बनने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 8 दिन के दौरे पर एक बार फिर ग्लोबल साउथ के साथ भारत के विजन और रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित किया।

घाना: तीन दशक में भारतीय पीएम की पहली यात्रा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के पहले दिन 2 जुलाई को घाना पहुंचे। यह तीन दशक में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली घाना यात्रा थी। कोविड महामारी के दौरान भारत ने मुश्किल समय में भी अपने मित्र घाना को वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत 6 लाख कोविड वैक्सीन दी थीं। दोनों देश ने विदेश मंत्रालय लेबल पर जॉइंट कमीशन की स्थापना, पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में साझेदार, सांस्कृतिक पर्यटन और उत्पादों के गुणवत्ता नियम से जुड़े 4 क्षेत्रों में अहम समझौते भी किए। प्रधानमंत्री मोदी ने घाना की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। उन्होंने एजेंडे को आकार देने में अफ्रीका की बढ़ती भूमिका का भी जिक्र किया।

पोर्ट ऑफ स्पेन में पीएम मोदी का स्वागत चौताल की गूंज और ढोलक, तासा, झाल की थापों के साथ हुआ।

40 फीसदी भारतीय मूल की आबादी वाले त्रिनिदाद एंड टोबैगो में पीएम मोदी

घाना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 और 4 जुलाई को त्रिनिदाद एंड टोबैगो पहुंचे। ये यात्रा पिछले 26 वर्ष में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। त्रिनिदाद की करीब 13.6 लाख की आबादी में 40 फीसदी भारतीय मूल के लोग हैं। पीएम मोदी की यह यात्रा ऐसे समय पर हुई, जब त्रिनिदाद 1845 में पहली बार भारतीयों के यहां आगमन की 180वीं वर्षगांठ मना रहा है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के निमंत्रण पर हुई इस यात्रा के दौरान दोनों देश के प्रधानमंत्रियों ने व्यापक द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला त्रिनिदाद एंड टोबैगो कैरेबियन क्षेत्र का पहला देश बना। दोनों देशों ने इंडिया स्टैक के तहत डिजिलॉकर-साइन और जीईएम जैसे प्लेटफॉर्म पर सहयोग बढ़ाने की बात कही। त्रिनिदाद ने भूमि पंजीकरण प्रणाली के डिजिटलीकरण में भारत से सहायता मांगी। प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल शिक्षा योजना को समर्थन देने के लिए 2 हजार लैपटॉप भेंट किए तो साथ ही 10 लाख अमेरिकी डॉलर मूल्य की कृषि मशीनरी की सहायता दी। संस्कृति के क्षेत्र में त्रिनिदाद के पुजारियों को प्रशिक्षण देने की घोषणा की, जो 'गीता महोत्सव' में भाग लेंगे।

नामीबिया में ऐतिहासिक स्वागत से अभिभूत पीएम मोदी ने खुद बजाया ढोल।

नामीबिया की राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी।

ब्राजील में भारतीय समुदाय के साथ पीएम।

भारत-नामीबिया के बीच रिश्तों का नया युग

अपने दौरे के अंतिम दिन 9 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी नामीबिया की राजधानी विंडहोक पहुंचे। ये उनका नामीबिया का पहला और भारत के किसी प्रधानमंत्री का तीसरा दौरा है। पीएम मोदी ने नामीबिया की संसद को संबोधित किया। उसमें स्वतंत्रता, समानता और न्याय के प्रहरी के रूप में उन्होंने दोनों देश से वैश्विक दक्षिण की बेहतरी के लिए काम करने का आह्वान किया, ताकि वहां के लोगों की आवाज न केवल सुनी जाए बल्कि उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को भी पूरी तरह साकार किया जा सके। राष्ट्रपति डॉ. नेटुम्बो नंदी-नदैतवाह ने पीएम मोदी का राजधानी विंडहोक स्थित स्टेट हाउस में स्वागत किया। दोनों नेताओं ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी और यूपीआई, कृषि, स्वास्थ्य और फार्मा, ऊर्जा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेता ने वार्ता के बाद स्वास्थ्य और उद्यमिता के क्षेत्र में दो समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया। इसके अलावा, यह घोषणा भी की गई कि नामीबिया आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल हो गया है। पीएम मोदी ने नामीबिया को अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया। वहीं नमीबिया यूपीआई तकनीक अपनाने के लिए लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है।

57 वर्ष में पहली बार अर्जेंटीना पहुंचे भारतीय प्रधानमंत्री

अपने दौरे के तीसरे पड़ाव में प्रधानमंत्री मोदी 5 जुलाई को लैटिन अमेरिकी देश अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स पहुंचे। यह 57 साल में भारत के किसी प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय अर्जेंटीना यात्रा है। यह भारत-अर्जेंटीना संबंधों के लिए महत्वपूर्ण वर्ष है क्योंकि दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माईलेई से मुलाकात की। दोनों के बीच जरूरी खनिजों, व्यापार-निवेश, ऊर्जा, कृषि सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई। बता दें कि अर्जेंटीना के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार है।

ब्राजील में शिव तांडव स्त्रोत के साथ ऐतिहासिक स्वागत

परस्पर विश्वास और मित्रता की 8 दशक पुरानी साझेदारी में नया रंग भरने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधिकारिक यात्रा पर ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया पहुंचे। यहां पीएम मोदी का स्वागत शिव तांडव स्त्रोत के साथ किया गया। अल्वोराडा पैलेस में ब्राजील के राष्ट्रपति लुईज इनासियो लूला दा सिल्वा के साथ मुलाकात में पीएम मोदी ने बहुआयामी महत्वपूर्ण साझेदारी के सभी पहलुओं पर चर्चा की। दोनों देश ने अगले पांच साल में द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब डॉलर (1.70 लाख करोड़ रुपये) तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी ने मजाकिया अंदाज में कहा-फुटबॉल ब्राजील की आत्मा है, तो क्रिकेट भारतीयों का जुनून। चाहे गेंद बाउंड्री पार जाए या गोलपोस्ट में, 20 अरब डॉलर की साझेदारी मुश्किल नहीं है।

क्या है ग्लोबल साउथ...

उत्तरी और दक्षिणी दुनिया को बांटने वाली रेखा जर्मनी के पूर्व चांसलर विल्हम 'विली' ब्रांट के विचारों से उभरी थी। 1980 में, ब्रांट की अध्यक्षता वाले एक आयोग ने 'नॉर्थ-साउथ : ए प्रोग्राम फॉर सर्वाइवल' नामक रिपोर्ट पेश की थी। इसमें दुनिया को 30 डिग्री उत्तर के अक्षांश के

आर-पार बांट दिया गया। यह अक्षांश अमेरिका और मेक्सिको के बीच से होकर पूरे अफ्रीका के ऊपर से और फिर सीधे यूरोप से गुजरते हुए ऊपर उठकर चीन को भी शामिल कर लेता है। लेकिन, इसके बाद घुमाव के साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़ देता है। यानी भूगोल की कसौटी विपरीत जाकर यह समृद्ध उत्तर और गरीब, जूझते, विकासशील दक्षिण का विभाजन कर देता है। इसके बाद बीच के पांच दशकों में इसे कई नाम दिए गए- तीसरी दुनिया, विकासशील दुनिया आदि। अब इसे 'ग्लोबल साउथ' कहा जाता है।

उपहारों में भारतीय संस्कृति की झलक

राम मंदिर की प्रतिकृति, सरयू के जल का कलश और मधुबनी पेंटिंग के साथ रिश्तों का अपनापन

पीएम मोदी ने त्रिनिदाद एंड टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर को अयोध्या के श्रीराम मंदिर की चांदी से बनी भव्य प्रतिकृति और सरयू नदी के जल से भरा कलश उपहार में दिया। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली को उन्होंने चांदी का शेर गिफ्ट किया। अर्जेंटीना की उपराष्ट्रपति विक्टोरिया विलारुएल को मधुबनी पेंटिंग भेंट की। घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा को बिदरी कलाकृति से सजाए गए फूलदान और उनकी पत्नी को चांदी का पर्स गिफ्ट में दिया।

पीएम मोदी को 8 दिन में 4 देश का सर्वोच्च सम्मान

आठ दिन के विदेश दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी को चार देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। घाना ने उन्हें 'द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना', त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने 'ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो', ब्राजील ने 'द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस' और नामीबिया ने 'ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिसिएंट वेलविचिया मिराबिलिस' से सम्मानित किया। पीएम मोदी त्रिनिदाद एवं टोबैगो के इस सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी नेता और नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं।

नामीबिया

ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिसिएंट वेलविचिया मिराबिलिस

घाना

ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना

त्रिनिदाद एंड टोबैगो

द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो

ब्राजील

द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस

इस वर्ष इन देशों ने भी किया सम्मानित

मॉरीशस
ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन

साइप्रस
ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोस-III

श्रीलंका
मित्र विभूषण पुरस्कार

अब तक 27 देशों का सम्मान

■ 2024

कुवैत : ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर

गयाना : ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस

बारबाडोस : ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस

डोमिनिका : द डोमिनिका अवॉर्ड ऑफ ऑनर

नाइजीरिया : ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर

रूस : ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल

भूटान : ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो

■ 2023

ग्रीस : ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर

फ्रांस : ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर

मिस्र : ऑर्डर ऑफ द नाइल

फिजी : कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी

पापुआ न्यू गिनी : ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहु

पलाऊ : एबाकल अवॉर्ड

■ 2020

संयुक्त राज्य अमेरिका : लीजन ऑफ मेरिट

■ 2019

यूएई : ऑर्डर ऑफ जायेद अवॉर्ड

मालदीव : ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन

बहरीन : किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रिनेसां

■ 2018

फिलिस्तीन : ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन

■ 2016

सऊदी अरब : द किंग अब्दुलअजीज सैश

अफगानिस्तान : स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्ला खान

रोजगार से राष्ट्र निर्माण

युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की नींव

भारत आज दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में नए कीर्तिमान गढ़ रहा है तो इसके मूल में नीतिगत सुधार के रूप में वे रिफॉर्म्स हैं, जिनकी नींव 2014 के बाद रखी गई। इन सुधारों का असर रोजगार के क्षेत्र में भी दिख रहा है। देश के युवाओं के हाथ में काम देने की पहल के तहत केंद्र सरकार ने रोजगार मेले समेत कई ऐसे कदम उठाए हैं, जिनसे उनमें आत्मविश्वास जागा है तो साथ ही जिम्मेदारी का नया भाव भी आया है। इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जुलाई को एक बार फिर रोजगार मेले के तहत 51 हजार से अधिक युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में पहला राष्ट्रीय रोजगार मेला 22 अक्टूबर 2022 को आयोजित किया गया। तब से 12 जुलाई, 2025 को आयोजित 16वें रोजगार मेले में सौंपे गए 51 हजार नियुक्ति पत्र सहित कुल 10 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र केंद्र सरकार की तरफ से सौंपे जा चुके हैं। इन रोजगार मेलों में नियुक्ति पत्र पाने वाले युवा सरकार के अलग-अलग विभागों में अपनी सेवा दे रहे हैं।

रोजगार मेला कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह आपके लिए जिम्मेदारियों की शुरुआत का दिन है। अलग-अलग भूमिकाओं के बावजूद उनका साझा लक्ष्य 'नागरिक प्रथम' के सिद्धांत पर आधारित राष्ट्र सेवा है। विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी और सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ भारत में घरेलू और वैश्विक स्तर पर भविष्य को आकार देने की क्षमता है। यही विशाल युवा शक्ति भारत की सबसे बड़ी पूंजी है और सरकार इस पूंजी पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हुए इनके विकास पर जोर दे रही है।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी हालिया विदेश यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने पिछले दिनों जिन देशों की यात्रा की वहां उन्होंने भारत के युवाओं की शक्ति का प्रदर्शन देखा है। यही वजह है कि इन यात्राओं के दौरान हुए समझौतों में युवाओं को प्राथमिकता दी गई है, जिसका लाभ देश-विदेश में रह रहे भारतीय युवाओं को मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा "ये पहल न केवल भारत की वैश्विक आर्थिक

विकास का जो ये महायज्ञ चल रहा है, गरीब कल्याण और रोजगार निर्माण का जो मिशन चल रहा है, आज से इसको आगे बढ़ाने का दायित्व आपका भी है। सरकार रुकावट नहीं बननी चाहिए, सरकार विकास की प्रोत्साहक बननी चाहिए।

–नरेंद्र मोदी, **प्रधानमंत्री**

इन कदमों से बढ़ रहे हैं रोजगार

11 लाख करोड़ रुपये का है भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण।

- पहले देश में मोबाइल फोन बनाने वाली दो से चार इकाई थी आज लगभग 300 इकाई है।

1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक का है देश का रक्षा निर्माण उत्पादन।

- ऑटोमोबाइल क्षेत्र में केवल पांच वर्ष में 40 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है।

4 करोड़ पक्के घर बनाए गए और और तीन करोड़ निर्माणाधीन है।

- 12 करोड़ शौचालय का निर्माण और 10 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन।

3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के मिशन पर आगे बढ़ रही है सरकार।

- एक दशक में 90 करोड़ से अधिक लोग सरकार के कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में आए।

निजी क्षेत्र में रोजगार पर भी सरकार का फोकस

पिछले कुछ वर्ष में पीएलआई (उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन) योजना के माध्यम से देश भर में 11 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं। भारत सरकार अब निजी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर और ध्यान केंद्रित कर रही है। यही वजह है कि रोजगार से जुड़ी एक नई प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत सरकार निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपये प्रदान करेगी। दूसरे शब्दों में कहें तो सरकार उनकी पहली नौकरी के पहले वेतन में योगदान देगी। इसके लिए सरकार ने लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इस योजना से लगभग 3.5 करोड़ नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

रोजगार मेलों में अब तक 10 लाख से ज्यादा को नौकरी

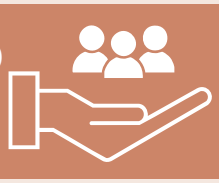

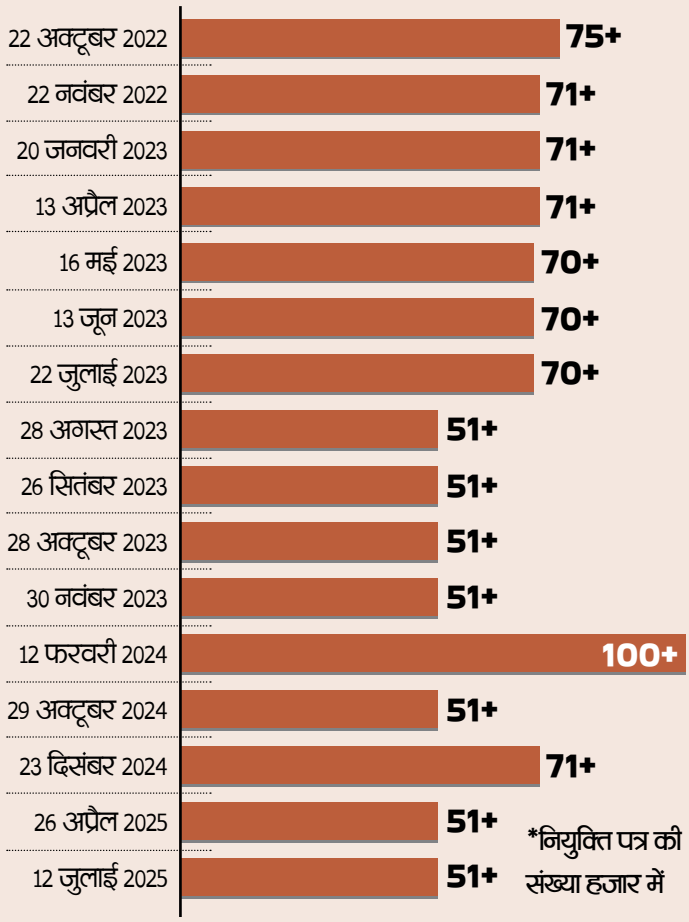

स्थिति को मजबूत करेंगी, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में भारतीय युवाओं के लिए सार्थक अवसर भी पैदा करेंगी। 21वीं सदी में रोजगार की प्रकृति तेजी से बदल रही है। केंद्र सरकार की अनगिनत योजनाओं का ही असर है कि पिछले 10 वर्ष में ही 25 करोड़ लोग गरीबी से बहार आए हैं और यह रोजगार के अवसर मिलने की वजह से ही संभव हो पाया है।" ■

केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय

देश के 100 जिलों के लिए धन-धान्य कृषि योजना मंजूर

देश के अन्नदाताओं को हर कदम पर सुविधा के साथ 21वीं सदी के हिसाब से विकास योजनाओं को आकार देना केंद्र सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। अपनी इसी प्रतिबद्धता के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जहां कम कृषि उत्पादन वाले 100 जिलों में किसानों के हित में प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना को मंजूरी दी तो वहीं वर्तमान समय की एक बड़ी जरूरत बन कर उभरी रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने की दिशा में भी किए दो महत्वपूर्ण निर्णय...

निर्णय : 1.7 करोड़ से ज्यादा किसानों के लाभ वाली धन-धान्य कृषि योजना मंजूर।

प्रभाव : प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना छह साल की अवधि के लिए है। इसके तहत हर वर्ष 24,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें 100 जिले शामिल होंगे, जिनका चयन कम उत्पादकता, कम फसल चक्र और कम लोन डिस्ट्रिब्यूशन जैसे तीन प्रमुख मानकों के आधार पर किया जाएगा। हर राज्य से कम से कम एक जिले का चयन जरूर किया जाएगा।

- यह योजना नीति आयोग के 'आकांक्षी जिला' कार्यक्रम से प्रेरित है, लेकिन यह खासतौर से कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों पर केंद्रित है। केंद्रीय बजट में घोषित यह कार्यक्रम 11 विभाग की 36 मौजूदा योजनाओं को एकीकृत करेगा और फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने में मदद देगा।
- पीएम धन-धान्य कृषि योजना से फसल के बाद भंडारण में वृद्धि होगी, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी। इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलने की संभावना है।
- योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी के लिए जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर समितियां गठित की जाएंगी। साथ ही समिति में प्रगतिशील किसान भी सदस्य होंगे। नीति आयोग भी जिला योजनाओं की समीक्षा और मार्गदर्शन करेगा। इसके अलावा, प्रत्येक जिले में नियुक्त केंद्रीय नोडल अधिकारी भी नियमित आधार पर योजना की समीक्षा करेंगे।

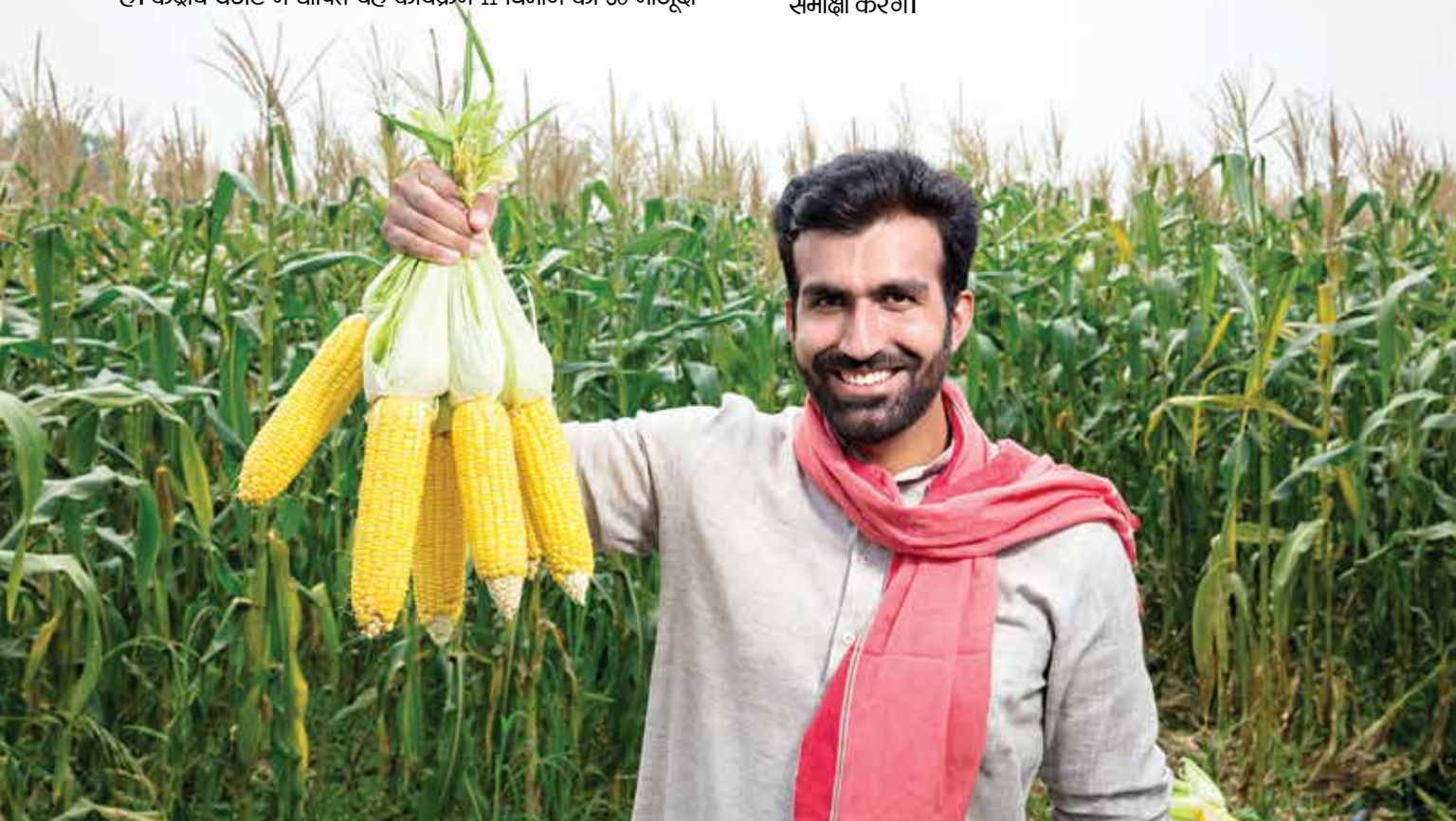

ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की वापसी पर मंत्रिमंडल की बधाई

15 जुलाई को भारत की अनंत आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्रा से सकुशल धरती पर लौटे हैं। ये समूचे देश के लिए गर्व, गौरव और उल्लास का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के साथ मिलकर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटने का अभिनंदन किया, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिन का ऐतिहासिक मिशन पूरा किया। मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए इसरो के साथ वैज्ञानिक और इंजीनियरों की पूरी टीम को हार्दिक बधाई दी। यह मिशन 25 जून 2025 को लॉन्च हुआ था, जिसमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला मिशन पायलट के रूप में शामिल हुए। इस मिशन के जरिए पहली बार कोई भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गया। यह भारत के स्पेस प्रोग्राम का एक नया अध्याय है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहते हुए ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने अनेक प्रयोग किए। यह इंटरनेशनल स्पेस कोऑपरेशन में भारत की बढ़ती लीडरशिप भूमिका का प्रमाण है।

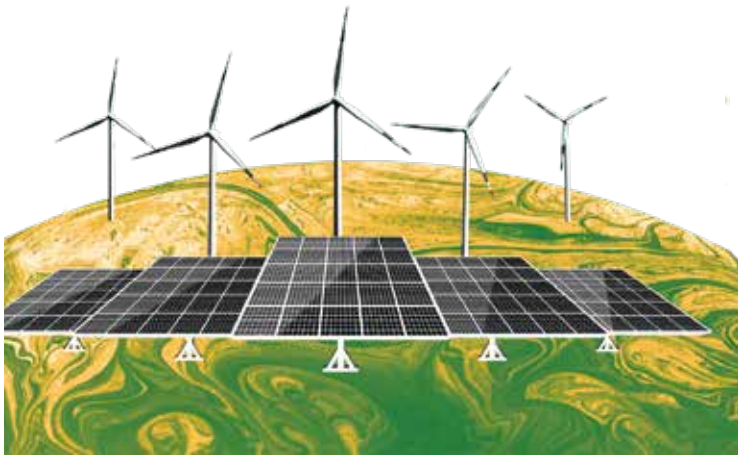

निर्णय : रिन्यूएबल एनर्जी में 20,000 करोड़ रुपये निवेश कर सकेगा एनटीपीसी।

प्रभाव : एनटीपीसी लिमिटेड को नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में निवेश के लिए मौजूदा सीमा से ऊपर जाकर 20,000 करोड़ रुपये तक निवेश की अनुमति दी गई है। पहले यह सीमा 7,500 करोड़ रुपये थी। यह निवेश एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, इसकी सहायक कंपनी और संयुक्त उपक्रमों के जरिए किया जाएगा। लक्ष्य है, वर्ष 2032 तक 60 गीगावॉट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता हासिल करना। यह कदम बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और पूरे देश में चौबीसों घंटे बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

निर्णय : अक्षय ऊर्जा के तीव्र विकास के उद्देश्य से एनएलसीआईएल के लिए निवेश की रियायत को मंजूरी।

प्रभाव : इस रणनीतिक निर्णय से एनएलसीआईएल अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड (एनआईआरएल) में 7,000 करोड़ रुपये का निवेश कर सकेगी। इन रियायतों का उद्देश्य एनएलसीआईएल के 2030 तक 10.11 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता विकसित करने और 2047 तक इसे 32 गीगावाट तक विस्तारित करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करना है। इस फैसले से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता के साथ कोयला आयात कम करने में मदद मिलेगी। वहीं, देशभर में 24 घंटे बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने के साथ ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने का सपना साकार होगा। ■

PMO India
@PMOIndia

आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर हमारी सोच समान है - zero tolerance and zero double standards.

हमारा स्पष्ट मत है कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है।

हम आतंकवाद और आतंकवाद के समर्थकों का कठोर विरोध करते हैं: PM @narendramodi

Rajnathsingh_in
@RajnathSingh_in

आज देश में नक्सलवाद की स्थिति यह है कि वह अब पूरे देश में सिर्फ 5-6 जिलों तक सिमट कर रह गया है और वहां भी उनका आतंक बहुत दिनों तक नहीं रहेगा: रक्षा मंत्री श्री @rajnathsingh

Amit Shah
@AmitShah

मोदी सरकार ने भारतीय न्याय प्रणाली में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने की दिशा में जिन तीन नए कानूनों की आधारशिला रखी थी, आज उन्हें देशभर में लागू हुए एक वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में नए कानूनों की एक वर्ष की उपलब्धियों पर संवाद किया।

Nitin Gadkari
@nitin_gadkari

We have successfully completed the 66.916 km long, 4-lane Greenfield Bandikui Spur, constructed at a capital cost of ₹2,016 crore. This strategically significant project provides direct, access-controlled connectivity between the Delhi–Vadodara Expressway and Jaipur —addressing the lack of a direct route that previously compelled commuters to take longer, fuel-intensive journeys.

Sarbananda Sonowal
@sarbanandsonwal

In the last 11 years under the Hon'ble PM Shri @narendramodi ji led, more than ₹ 6 lakh crore financial assistance has been given to the North East.

This amount was just ₹ 1.4 lakh crore in the 10 years of UPA Govt.

#11YearsofSeva

Dr Mansukh Mandaviya
@mansukhmandviya

नशे के खिलाफ, युवा होंगे एक साथ!

बाबा विश्वनाथ की धरती काशी से होने जा रहा नशा मुक्ति का आह्वान।

प्रधानमंत्री श्री @NarendraModi जी की सरकार द्वारा युवाओं को सशक्त करने के अभियान की दिशा में 18 से 20 जुलाई तक 'युवा आध्यात्मिक समिट' का होगा आयोजन।

#NashaMuktYuva

गुवाहाटी रेल की सीटी | कुतुब मीनार से ऊंचा पुल बना, आइजोल पहुंचेगी ट्रेन

मिज़ोरम में सपनों की ट्रेन का वेलकम, अब लिखेंगे तरक्की का मनोरम कल

स्टूडेंट्स, व्यापारी, टूरिस्ट... सभी को होगा फायदा

खनिज और तकनीक का प्रयोग हथियार के रूप में न हो : मोदी

रियो डी जेनेरियो, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी देश महत्वपूर्ण खनिजों और तकनीक का इस्तेमाल हथियार के रूप में न करे।

मोदी ने रविवार को बहुपक्षवाद, वित्तीय मामलों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आयोजित सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पारदर्शिता बनाए रखने और एआई के दुरुपयोग को रोकने के लिए वैश्विक मानकों के निर्माण का आह्वान किया।

ब्राजील की राजधानी में सोमवार को ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग (बाएं) और विदेश मंत्री एस जयशंकर।

पीएम मोदी को ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान 'नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस' से नवाजे गए

देश के बाहर भी यूपीआई का प्रभाव बढ़ा वैश्विक साझेदारियों से मिला नया विस्तार

नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने उपयोगकर्ता अनुभव बढ़ाने के लिए यूपीआई में नई सुविधाएं शुरू की हैं। इसमें क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट्स, लोन और इंश्योरेंस सेवाओं के एकीकरण और अन्य अनेक सुविधाएं शामिल हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की 3-4 जुलाई को त्रिनिदाद और टोबैगो यात्रा के दौरान यूपीआई की अंतरराष्ट्रीय पहुंच का नया उदाहरण देखने को मिला।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों ने डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने में गहरी रुचि व्यक्त की। त्रिनिदाद और टोबैगो यूपीआई को अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश बन गया है। दोनों देशों ने डिजिटल क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने और इंडिया

| सहयोग | प्रधानमंत्री मोदी आज ब्राजील के राष्ट्रपति लूला से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, दोनों देशों के बीच 1948 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे

भारत-ब्राजील के बीच रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ रही भागीदारी

अंतरिक्ष क्षेत्र में भी समझौता

2023 के बाद ब्राजील के राष्ट्रपति लूला से मोदी की कर चुके मुलाकातें हो चुकी

विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस-14 अगस्त

...जब इंसान बंटे, सामान बंटा

बंटे धरती-अंबर

भारत का विभाजन अभूतपूर्व मानव विस्थापन और मजबूरी में पलायन की दर्दनाक कहानी है। धार्मिक आधार पर एक हिंसक विभाजन के दुखद अध्याय के साथ यह इस बात की भी कहानी है कि कैसे एक जीवन शैली और वर्षों पुराने सह-अस्तित्व का युग अचानक और नाटकीय रूप से समाप्त हो गया। विस्थापितों का काफिला 10 से 27 मील तक लंबा था। बारिश, भूख और दंगों में कइयों को जान गंवानी पड़ी। इस विभीषिका में मारे गए लोगों का आंकड़ा 5 लाख बताया जाता है, लेकिन अनुमानतः यह 5 से 10 लाख के बीच है। पलायन के बीच अपने प्राण गंवाने वाले और विस्थापन का दर्द झेलने वाले लाखों भारतवसियों को नमन करने के लिए 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की शुरुआत...

60 लाख गैर-मुसलमान उस क्षेत्र से निकल आए, जो बाद में पश्चिमी पाकिस्तान बन गया।

65 लाख मुसलमान पंजाब, दिल्ली आदि के भारतीय हिस्सों से पश्चिमी पाकिस्तान चले गए।

20 लाख गैर-मुसलमान पूर्वी बंगाल, जो बाद में पूर्वी पाकिस्तान बना, वहां से निकल कर पश्चिम बंगाल आए। 1950 में 20 लाख लोग और प. बंगाल आए।

10 लाख मुसलमान प. बंगाल से पूर्वी पाकिस्तान चले गए।

विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हमें यह याद दिलाता रहेगा कि सामाजिक भेदभाव और वैमनस्य को मिटाने व एकता, सामाजिक समरसता और मानवीय संवेदनाओं को मजबूत करने की जरूरत है। – *नरेंद्र मोदी*, प्रधानमंत्री

न्यू इंडिया समाचार
पाक्षिक

आर.एन.आई, DELHIN/2020/78812, 1-15 अगस्त, 2025

आरएनआई DELHIN/2020/78812, दिल्ली पोस्टल लाइसेंस नंबर- DL (S)-1/3550/2023-25 डब्ल्यूपीपी संख्या- U (S)-98/2023-25, posting at BPC, Market Road, New Delhi - 110001 on 26-30 advance Fortnightly (प्रकाशन तिथि- 16 जुलाई 2025, कुल पृष्ठ-44)

प्रधान संपादक: धीरेन्द्र ओझा, प्रधान महानिदेशक, पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

प्रकाशक और मुद्रक: कंचन प्रसाद, महानिदेशक, केंद्रीय संचार ब्यूरो

कमरा संख्या-278, केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना भवन, द्वितीय तल, नई दिल्ली- 110003 से प्रकाशित

मुद्रण: जेके ऑफसेट ग्राफिक्स प्रा. लि., बी-278, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020